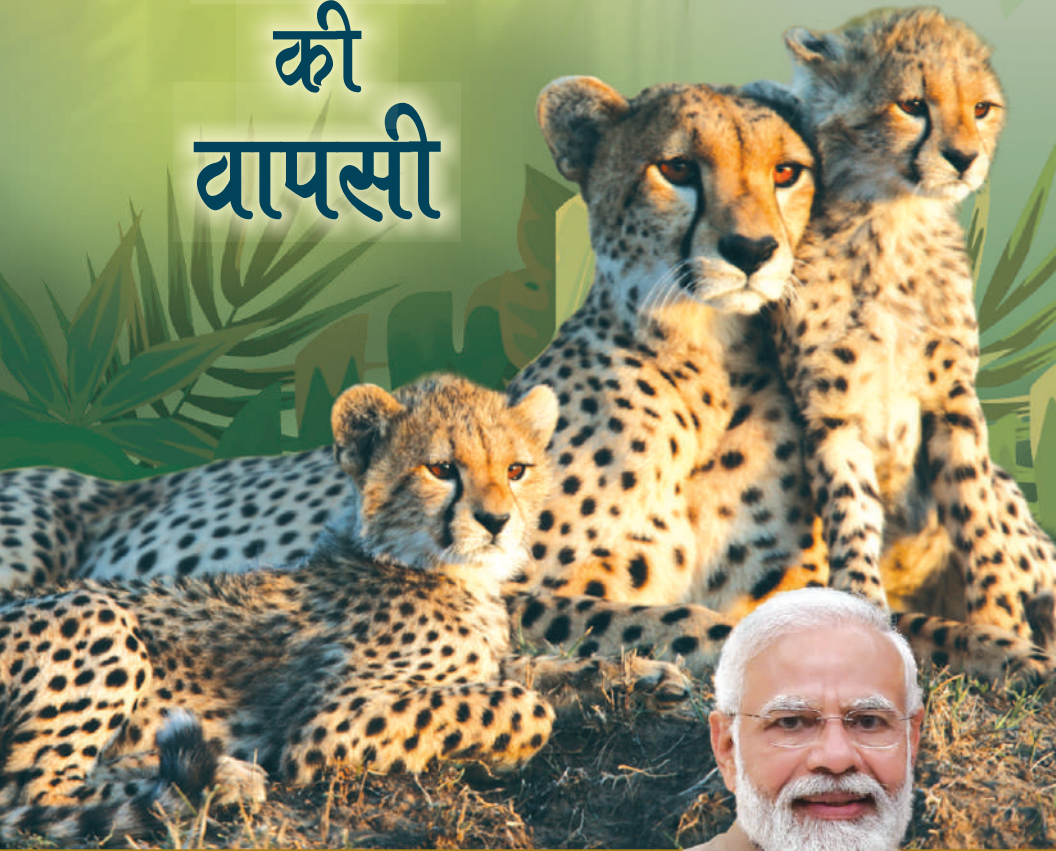


# चीतों की वापसी



## मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन

# सूची क्रम

01	प्रधानमंत्री का संदेश	1
02	प्रधानमंत्री द्वारा विशेष उल्लेख	13
2.1	भारत में चीतों की वापसी	14
2.1.1	भारत में चीता - एक आदर्श वन्य जीव संरक्षण एस.पी. यादव का लेख	16
2.2	पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और दर्शन	20
2.2.1	भारत की राष्ट्रनीति का विचार - एकान्त मानव दर्शन : मुकुल कनिटकर का लेख	22
2.3	भारतीय सांकेतिक भाषा: गौरव और पहचान का प्रतीक	24
2.3.1	ISL: समावेशी संचार का ध्वजवाहक - राजेश यादव का लेख	30
2.3.2	ISL के साथ समावेशन स्वप्न नहीं, बल्कि वास्तविकता : टी.के.एम. संदीप का लेख	32
2.4	स्वच्छ भारत : हर भारतीय का संकल्प	34
2.4.1	व्यवहार परिवर्तन और सार्वजनिक स्वच्छता की जिम्मेदारी का नया दौर : तेजस्वी सूर्या का साक्षात्कार	38
2.4.2	'कबाड़ से जुगाड़' : निष्प्रयोज्य सामग्री का उपयुक्त प्रयोग : ए.के. शर्मा का लेख	42
2.4.3	'स्टॉप कम्प्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग' अमित अमरनाथ का साक्षात्कार	44
2.5	लोकल के लिए वोकल - आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत	46
2.5.1	देश और फैशन के लिए खादी - रितु बेरी का लेख	52
2.6	सेवा परमो धर्म: जन भागीदारी से बदल रहा देश का भविष्य	54
2.6.1	टीबी-मुक्त भारत अभियान पर विराट कोहली के विचार	59
2.6.2	टीबी उन्मूलन के लिए जन-आंदोलन डॉ. विनोद पॉल का लेख	60
2.6.3	भारत में टीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है सामुदायिक उत्तरदायित्व - पूनम खेत्रपाल का लेख	62
2.6.4	शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में कम होता विभेद - प्रफुल पटेल का लेख	66
2.7	मिरेकल मिलेट्स	68
2.7.1	मिलेट्स के महत्व पर विकास खन्ना के विचार	70
03	प्रतिक्रियाएँ	73

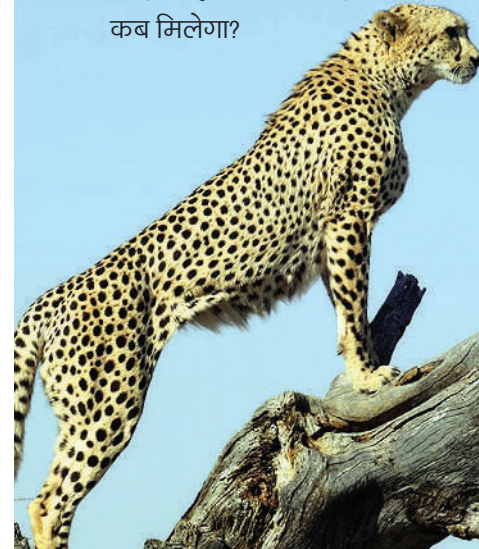
# प्रधानमंत्री का संदेश



## मेरे प्यारे देशवासियो, नमस्कार

पिछले दिनों जिस बात ने हम सब का ध्यान आकर्षित किया- वह है चीता। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेज़ेज आए हैं, वह चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ताजी हों या फिर तेलंगाना के एन. रामचंद्रन रघुरामजी, गुजरात के राजनजी हों या फिर दिल्ली के सुब्रतजी। देश के कोने-कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियाँ जताई हैं। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं- यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदीजी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा?

**साथियो!** एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनीटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल-मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएँगे, लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ-कुछ काम सौंप रहा हूँ, इसके लिए MyGov के प्लेटफॉर्म पर एक कम्पटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूँ। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए। क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया



भारत में  
**चीतों**  
की वापसी

जाए। वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परम्परा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज, हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएँ आखिर इंसानों को एनीमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हमारी फंडामेंटल इयूटीज़ में भी तो रेस्पेक्ट फ़ॉर एनीमल्स पर ज़ोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कम्पटीशन में ज़रूर भाग लीजिए, क्या पता ईनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए।

**मेरे प्यारे देशवासियो,** आज 25 सितम्बर को देश के प्रखर मानवतावादी, चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्यायजी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे-जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयालजी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी-बड़ी उथल-पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे।



पं. दीनदयाल उपाध्याय  
25 सितम्बर, 1916 - 11 फरवरी, 1968



इसीलिए उन्होंने 'एकात्म मानव दर्शन' और 'अंत्योदय' का एक विचार देश के सामने रखा, जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयालजी का 'एकात्म मानव दर्शन' एक ऐसा विचार है, जो विचारधारा के नाम पर द्वंद और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, 'आत्मवत् सर्वभूतेषु', अर्थात्, हम जीव मात्र को अपने समान मानें, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयालजी ने हमें सिखाया। एक तरह से आज़ादी के बाद देश में जो हीनभावना थी, उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जाग्रत किया। वो कहते भी थे, 'हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है, जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे।' इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विज्ञान निर्मित किया था।

दीनदयाल उपाध्यायजी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना, अन्तिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आज़ादी के अमृतकाल में हम दीनदयालजी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी।

**मेरे प्यारे देशवासियो,** आज से तीन दिन बाद, यानी 28 सितम्बर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएँगे। भगत सिंहजी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंहजी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

साथियो, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएँ, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए

प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्यपथ पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति की स्थापना के ज़रिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूँगा, अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितम्बर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे।

वैसे मेरे प्यारे देशवासियो, आप सभी के पास 28 सितम्बर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा, लेकिन मुझे पता है, आपका जोश चार गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दो शब्द हैं- सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश! हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उसे हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें।

**मेरे प्यारे देशवासियो,** कहते हैं- जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं, जो किसी-ना-किसी



शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साधियों के लिए सबसे बड़ा सम्बल होती है, साइन लैंग्वेज, लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव-भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडिया साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक दस हजार वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। दो दिन पहले यानी 23 सितम्बर को साइन लैंग्वेज डे पर, कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफ़ी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है, उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने, इंडिया साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं, यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारम्भ हुआ था, अब उसका लाभ

लाखों मेरे दिव्यांग भाई-बहनों को होने लगा है। हरियाणा की रहने वाली पूजाजी तो इंडिया साइन लैंग्वेज से बहुत खुश हैं। पहले वो अपने बेटे से ही संवाद नहीं कर पाती थीं, लेकिन 2018 में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद, माँ-बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। पूजाजी के बेटे ने भी साइन लैंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरीटेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया। इसी तरह, टिकाजी की छह साल की एक बिटिया है, जो सुन नहीं पाती है। टिकाजी ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का कोर्स कराया था, लेकिन उन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्यूनिकेट नहीं कर पाती थी। अब टिकाजी ने भी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँ-बेटी अब आपस में खूब बातें किया करती हैं। इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ केरला की मंजूजी को भी हुआ है। मंजूजी, जन्म से ही सुन नहीं पाती हैं, इतना ही नहीं, उनके पैरेंट्स के जीवन में भी यही स्थिति रही है। ऐसे में साइन लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी है। अब तो मंजूजी

# भारतीय सांकेतिक भाषा:



## दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज का निर्माण

ने खुद ही साइन लैंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला ले लिया है।

साधियो, मैं इसके बारे में 'मन की बात' में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि इंडिया में साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साधियों की अधिक-से-अधिक मदद कर सकेंगे। भाइयो और बहनो! कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेमकोश की एक कॉपी भी मिली है। हेमकोश असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्शनरीज में से एक है। यह 19वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका सम्पादन प्रख्यात भाषाविद् हेमचन्द्र बरुआजी ने किया था। हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10 हजार पन्नों का है और यह 15 वाल्यूम्स से भी अधिक में प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें एक लाख से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है। मैं इस संवेदनशील प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ। इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साधियों का कौशल और सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम

लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं, जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को ज़मीनी स्तर पर बढ़ावा देने में जुटे हैं। इससे दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिलता है।

**मेरे प्यारे देशवासियो,** मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में, मैं 'मन की बात' के सभी श्रोताओं



# जोश

## आज भी हर भारतीय के दिल में पूरा है

### #सर्जिकल स्ट्राइक



को ज़रूर बताना चाहता हूँ। साथियो, अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं और वो बचपन से ही हार्ट की गम्भीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल तीन महीने की थी, तभी उसे ओपेन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माता-पिता ने कभी हार मानी। अन्वी के माता-पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अन्वी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अन्वी को पानी का गिलास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बाँधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें सिखाना शुरू किया। कौन-सी चीज़ की जगह कहाँ है, कौन-सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की इच्छाशक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता-पिता को भी बहुत हौसला मिला। उन्होंने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। मुसीबत इतनी गम्भीर थी कि

अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी, ऐसी परिस्थिति में उनके माता-पिताजी ने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी, लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। अन्वी आज देशभर के कम्पैटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया। अन्वी ने योग को आत्मसात कर जीवन को आत्मसात किया। अन्वी के माता-पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है, अब उसका सेल्फ कान्फिडेंस गज़ब का हो गया है। योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की ज़रूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूँगा कि देश-विदेश में मौजूद, 'मन की बात' के श्रोता अन्वी को योग से हुए

लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें, मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है, जो योग के सामर्थ्य को जाँचना-परखना चाहते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके, योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च, दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज़्यादा कारगर है, विशेषकर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन-संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को रिकोगनाइज़ किया है, उसे सम्मानित किया है। ये प्रयास है, वर्ष 2017 में शुरू किया गया 'इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव' इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से जूझ रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। जिस तरह इस इनिशिएटिव ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान अपनी

ओर खींचा है, वो अभूतपूर्व है। ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है, उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मैं इस इनिशिएटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया।

साथियो, मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है - चाहे वो समुद्र हो, नदी हो या तालाब हो। भारत का भी सौभाग्य है कि करीब साढ़े सात हज़ार किलोमीटर (7500 किलोमीटर) से अधिक लम्बी कोस्टलाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अटूट रहा है। यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है। भारत के अलग-अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते-फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खानपान लोगों को खूब आकर्षित करता है, लेकिन इन मज़ेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है। हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, मरीन इको सिस्टम्स के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है तो दूसरी ओर हमारे बीचों पर फ़ैली गंदगी परेशान



करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गम्भीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश 'स्वच्छ सागर - सुरक्षित सागर' इसके बारे में बात करना चाहूँगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितम्बर को विश्वकर्मा जयंती के दिन सम्पन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनिंग डे भी था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जनभागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे ढाई महीने तक सफ़ाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लम्बी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाड़ा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में तीन दिन के अंदर 20 हज़ार से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आस-पास के लोगों को भी 'स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर' के

लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने, इस अभियान में हिस्सा लिया।

इलेक्ट्रेड ऑफ़ीशियल्स, खासकर शहरों के मेयर और गाँवों के सरपंचों से जब मैं संवाद करता हूँ, तो ये आग्रह ज़रूर करता हूँ कि स्वच्छता जैसे प्रयासों में लोकल कम्यूनिटीज़ और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करें, इन्वोवेटिव तरीके अपनाएँ।

बेंगलुरु में एक टीम है - यूथ फ़ॉर परिवर्तन, पिछले आठ सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों को लेकर काम कर रही है। उनका मोटो बिलकुल क्लीयर है - 'स्टोप कम्प्लेनिंग स्टार्ट एक्टिंग' इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से ज़्यादा जगहों का सौंदर्यीकरण किया है। हर स्थान पर 'यूथ फ़ॉर परिवर्तन' के अभियान ने 100 से डेढ़ सौ नागरिकों को जोड़ा है। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है। इस कार्य में कचरा तो हटाया ही जाता है, दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेज़ बनाने का काम भी होता है। कई जगहों पर तो आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्केचेज़ और उनके इंस्पीरेशनल कोट्स भी देख सकते हैं। बेंगलुरु के यूथ फ़ॉर परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरठ के

'कबाड़ से जुगाड़' अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्ट्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और इम जैसी बेकार हो चुकी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्च में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूँ।

**मेरे प्यारे देशवासियो,** इस समय देश में चारों ओर उत्सव की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप 'माँ शैलपुत्री' की उपासना करेंगे। यहाँ से नौ दिनों का नियम-संयम और उपवास, फिर विजयदशमी का पर्व भी होगा, यानी एक तरह से देखें तो हम पाएँगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ-साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दीवाली का भी पर्व आने वाला है।

**साथियो,** बीते वर्षों से हमारे त्योहारों

के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है - 'वोकल फॉर लोकल' का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। **आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैण्डीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ-साथ लोकल सामान ज़रूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है, जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका ये है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें, उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें।**

इस समय यह अभियान इसलिए भी खास है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो सही मायने में आज़ादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस बार खादी, हैंडलूम या हैण्डीक्राफ्ट, इस प्रोडक्ट को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हमने देखा

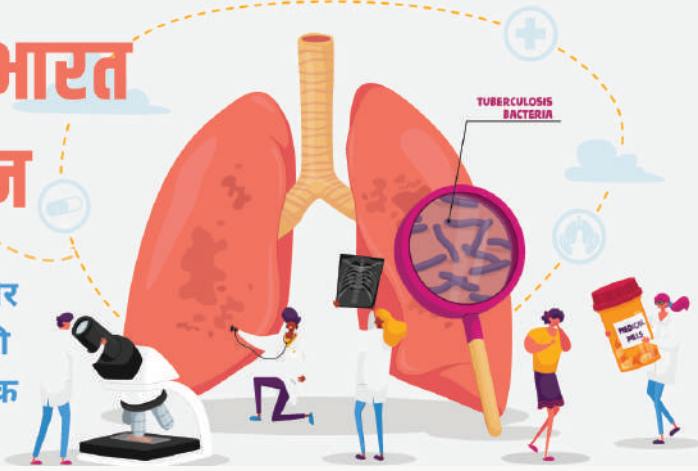
**स्वच्छ सागर  
सुरक्षित सागर**

**खादी  
के साथ बनें लोकल  
के लिए वोकल**



# टीबी-मुक्त भारत अभियान

समाज सेवा और जनभागीदारी की भावना का प्रतीक



है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए, हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन-प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के, ऐसे कितने ही पारम्परिक बैग्स का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी खयाल रखें।

**मेरे प्यारे देशवासियों,** हमारे शास्त्रों में कहा गया है –

*‘परहित सरिस धरम नहीं भाई’*

यानी दूसरों का हित करने के समान, दूसरों की सेवा करने, उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में, समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आगे

आकर किसी ना किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल, ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका आधार जनभागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण से ही, सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जनभागीदारी की इस शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत ज़रूर टीबी से मुक्त हो जाएगा।

साथियो, केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरण जानने को मिला है, जो मन को छू लेता है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जिनु रावतीयाजी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे ग्राम दत्तक कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गाँवों को गोद लिया है। इसमें जिनुजी का गाँव भी शामिल है। मेडिकल के ये छात्र, बीमारी से बचने के लिए गाँव के लोगों को जागरूक करते हैं, बीमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी

जानकारी देते हैं। परोपकार की ये भावना गाँवों में रहने वालों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आई है। मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ।

साथियो, ‘मन की बात’ में नए-नए विषयों की चर्चा होती रहती है। कई बार इस कार्यक्रम के ज़रिए हमें कुछ पुराने विषयों की गहराई में भी उतरने का मौक़ा मिलता है। पिछले महीने ‘मन की बात’ में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल मिलेट्स इयर’ के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे डेरों पत्र मिले हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाले पारम्परिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई-बुक तैयार करनी चाहिए, जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेज़ और अपने अनुभवों को साझा कर सकें, इससे इंटरनेशनल मिलेट्स इयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक

इन्साइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे MyGov पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं।

साथियो, ‘मन की बात’ में इस बार इतना ही, लेकिन चलते-चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 29 सितम्बर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा ही ख़ास मौक़ा है, क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन, कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूँगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को ज़रूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएँ। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले महीने ‘मन की बात’ में नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाक़ात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।

मन की बात सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।





# मन की बात

प्रधानमंत्री द्वारा विशेष उल्लेख



# भारत में चीतों की वापसी

भारत एक बार फिर चीतों की आलीशान उपस्थिति का घर बना है। दुनिया का सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर चीता, मुख्य रूप से शिकार और प्राकृतिकवास के नुकसान के कारण, 1952 में भारत से लुप्त हो गया था। राष्ट्रीय संरक्षण नैतिकता और लोकाचार के लिए चीतों के संरक्षण का बहुत विशेष महत्त्व है। इसलिए 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत, जो बड़े जंगली माँसाहारियों के लिए दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय स्थानान्तरण परियोजना है, भारत सरकार का लक्ष्य चीता को वापस लाना है।



01 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 17 सितम्बर, 2022 को जंगली चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया।

02 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनों नेशनल पार्क में दो रिलीज़ पॉइंट्स पर छोड़ा गया।

03 8 चीतों में से 5 मादा और 3 नर चीते हैं।



## क्या आप जानते हैं?

'चीता' नाम (एसिनोनिक्स जुबेटस) की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और इसका अर्थ है 'चितीदार'।

अपनी रफ़्तार के कारण पहचाने जाने वाले चीता की गति को अधिकतम 114 किमी / घंटा मापा गया है और वे नियमित रूप से 80-100 किमी/घंटा के वेग तक पहुँचते हैं।

## प्रतियोगिताएँ

चीता पुनः परिचय परियोजना के लिए एक नाम सुझाएँ

पारंपरिक प्रकृति, भारतीय विरासत और संस्कृति से प्रेरित चीतों के नाम सुझाएँ

जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के महत्त्व को साझा करें



भाग लेने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

# भारत में चीतों के पुनः परिचय से

01

भारत में खुले जंगल और घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद होगी

02

जैव विविधता के संरक्षण में मदद होगी और जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा

03

पर्यावरण विकास और पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी



भारत में चीतों की वापसी से पर्यावरण की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 93वें 'मन की बात' सम्बोधन में चीतों को भारत वापस लाने की खुशी और सामूहिक गौरव को देश के साथ साझा किया। इसके साथ, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित प्रतियोगिताओं की एक इंटरैक्टिव श्रृंखला में भाग लें और चीतों को देखने के लिए एक यात्रा जीतने का एक विशेष अवसर प्राप्त करें!

# भारत में चीता – एक आदर्श वन्य जीव संरक्षण



**डॉ. एस. पी. यादव**

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण  
पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

17 सितम्बर, 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा कूनों राष्ट्रीय उद्यान में चीता (एसियोनिक्स जुबेटस) छोड़ा जाना सभी के लिए खुशी का पल था। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में चीता का आगमन, आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हुआ है। चीतों को एक महाद्वीप के जंगल से दूसरे महाद्वीप के जंगल में ला कर बसाना भी अपने-आप में एक ऐतिहासिक घटना है। नामीबिया से 8 चीतों को एक चार्टर्ड मालवाहक विमान से ला कर कूनों राष्ट्रीय उद्यान के एकांत बाड़ों में छोड़ा गया है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद 12 और चीते लाने के प्रयास भी जारी हैं। पहली बार एक जगह से दूसरी जगह ला कर बसाए गए इन चीतों की भारतीय जलवायु और पर्यावास के अनुकूल ढलने, शिकार करने और जीवित रहने की क्षमता की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के बाद ही अगले 5 वर्षों और उसके बाद ही इनके सफल प्रजनन

के बारे में निर्णय लिया जाएगा ताकि इनकी संख्या 40-45 तक की जा सके।

चीतों को भारत में फिर से बसाया जाना, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण के प्रति देश की निष्ठा और प्रतिबद्धता ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी बताता है कि देश नैतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक साधनों के संदर्भ में अपनी प्राकृतिक विरासत बहाल करने के लिए भी कटिबद्ध है।

इस महत्वपूर्ण प्रयास के पीछे का इतिहास हमें 1952 में ले जाता है, जब वन्यजीव मंडल की पहली बैठक में स्वीकार किया गया था कि देश में चीता लुप्तप्राय हो चुका है। इसी बैठक में चीता संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दिए जाने पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया गया। इसके बाद ही ईरान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ इस बारे में बातचीत शुरू हुई।

भारत में चीते विलुप्त होने का परिणाम यह हुआ कि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत वैज्ञानिक कारणों अथवा मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने की स्थिति के अलावा, हर प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार और उन्हें पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारत में वानिकी और वन्यजीव संरक्षण के तौर-तरीकों में बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र बहाल करने की रणनीति के तहत बड़े माँसाहारी जानवरों को फिर से बसाया जाना शामिल है। भारत में चीता एकमात्र ऐसा बड़ा माँसाहारी प्राणी है, जो अपना अत्यधिक शिकार होने और पर्यावास खो जाने के कारण लुप्त हुआ। जंगल के एक बड़े शिकारी जानवर को फिर से बसा

देने से खोया हुआ पारिस्थितिक तंत्र एक बार फिर जीवंत होगा और पारिस्थितिक पिरामिड में भी संतुलन कायम हो सकेगा। यही नहीं, शुष्क घास के मैदानों और मुक्त वन पारिस्थितिक तंत्र तथा चीता लुप्त होने के साथ ही लुप्त हुई अन्य प्रजातियों की विविधता में भी जान फूँकी जा सकेगी।

1952 से और फिर 2009 से निरंतर प्रयास करके भारत में चीता आबादी शुरू करने की दिशा में एक ठोस मंच तैयार किया गया। इस लक्ष्य को लेकर हुए विचार-विमर्श के बाद विस्तृत सर्वेक्षण करके उन सम्भावित स्थलों की पहचान की गई; जहाँ इन्हें फिर से बसाया जा सकता था। आईयूसीएन के दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रजातियों की व्यवहार्यता, उपयुक्त आवास, नष्ट न हो सकने वाले स्थान और शिकार के लिए पर्याप्त जीव-जंतुओं का आधार ध्यान में रखते हुए 10 सम्भावित स्थलों पर विचार किया गया। इनमें मध्य प्रदेश का कूनों राष्ट्रीय उद्यान, न्यूनतम सुधार के साथ सभी मानदंड पूरा करने में सबसे उपयुक्त माना गया।

748 वर्ग किमी का कूनों राष्ट्रीय उद्यान, 6,800 वर्ग किमी में फैले श्योपुर-शिवपुरी शुष्क पतझड़ वाले मुक्त वन का हिस्सा है। शिकार योग्य जानवरों के घनत्व के आधार पर यहाँ अधिकतम 21 चीते रह सकते हैं।

भारत में एक बार फिर से चीते की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पूरी निष्ठा से हुए प्रयासों की बदौलत नामीबिया और भारत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्मान, सम्प्रभुता, समानता तथा दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखने के सिद्धांतों पर आधारित वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए परस्पर लाभकारी सम्बन्ध विकसित किए जाएँगे।

दोनों देशों की तकनीकी विशेषज्ञता की मदद से आठ चीते (5 मादा और 3 नर) सफलतापूर्वक भारत लाकर खुले बाड़े में छोड़े गए।

प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में देश में एक बार फिर से चीते आने पर नागरिकों के बीच पैदा हुई उत्सुकता को रेखांकित किया। लोगों की इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अनुरोध किया कि इस पहल को एक नाम दिए जाने के बारे में अपने सुझाव दें और यहाँ आए सभी चीतों के पारम्परिक अथवा अपने-अपने समाज की संस्कृति से जुड़े नाम सुझाएँ।

हमारे संविधान में निर्धारित प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, इसे बेहतर बनाना और हर जीव-जंतु के लिए करुणा रखना हमारा कर्तव्य है। आइए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत के जंगली इलाके में छोड़े गए चीतों के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करें। इसके लिए, आस-पास के सभी गाँवों में 'चीता मित्र' नियुक्त किए गए हैं तथा लोगों और छात्रों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है।

'चीता मित्र' के बारे में अधिक जानने के लिए QR कोड स्कैन करें।





## 'चीता मित्र' कौन हैं?



लगभग 70 वर्षों के बाद भारत में चीतों के पुनः परिचय के साथ, सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के सुचारू रूप से बसने के उपाय किए हैं।

इनमें से एक उपाय है 'चीता मित्र'।



स्थानीय आबादी को बड़ी बिल्लियों से परिचित कराने और उन्हें चीते और इसकी विशेषताओं से अवगत कराने के लिए वन अधिकारियों के पास स्कूल शिक्षकों, ग्राम प्रधानों और पटवारियों सहित 51 गाँवों के लगभग 400 चीता मित्र हैं।



जानवरों के जंगल से बाहर निकलने जैसे सभी सम्भावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, चीतों की सुरक्षा के बारे में अधिकारियों को सचेत करने के लिए चीता मित्र नियुक्त किए गए हैं।



हालाँकि इन चीता मित्रों का मुख्य उद्देश्य जानवरों और ग्रामीणों की सुरक्षा है, उन्हें स्थानीय आबादी में 'जानवर का शिकार या नुकसान न करने' और 'चीते को तेंदुए से अलग कैसे करें' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है।

"मुझे आप (चीता मित्रों) पर पूरा विश्वास है कि आप कठिनाई का सामना करेंगे, लेकिन इन चीतों को किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करने देंगे। इसलिए मैं भरोसे के साथ इन 8 चीतों की ज़िम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ! मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।"

- पीएम नरेन्द्र मोदी (चीता मित्रों के साथ बातचीत में)

## चीता मित्र कहते हैं...

जब पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया, तो उन्होंने हमें 'चीता मित्र' होने की ज़िम्मेदारी दी। इन 8 चीतों की देखभाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस उद्देश्य के साथ कि यदि वे जंगल से बाहर आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तुरंत वन विभाग को सूचित करें और लोगों को किसी भी तरह से चीतों को नुकसान न पहुँचाने के लिए जागरूक करें, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे।

- रमेश

यह हमारी एकमात्र ज़िम्मेदारी है कि हम ग्रामीणों को जागरूक करें कि ये चीते किसी व्यक्ति पर हमला या नुकसान नहीं करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करें।

- सूर्या

मैं एक चीता मित्र हूँ और लोगों को यह बताना मेरा कर्तव्य है कि चीता हानिकारक नहीं है; वे हमारे 'मित्र' हैं। इसलिए हमें ग्रामीणों और चीतों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी देखभाल करनी चाहिए!

- चेतन

17 सितम्बर को जब पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क आए, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ बताईं। हमें, चीता मित्र के रूप में, स्थानीय आबादी के लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि चीतों का भारत आना हमारे लिए गर्व का क्षण है। यह हमारे लिए रोज़गार के विभिन्न अवसर पैदा करेगा; इसलिए हमें अपनी इच्छा से सब कुछ करना चाहिए कि हम चीतों की अच्छी देखभाल करें और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान न पहुँचाएँ।

- अरविंद

# पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और दर्शन

25 सितम्बर, 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गाँव में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री भगवती प्रसाद और श्रीमती रामप्यारी के सबसे बड़े पुत्र थे। कम उम्र में अपने माता-पिता को खो देने के बाद उनका पालन-पोषण उनके नाना और फिर उनके मामा ने किया। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद दीनदयाल जी ने अपने आस-पास की विरोधी ताकतों और कष्टों से ताकत हासिल कर एक अद्वितीय व्यक्तित्व का विकास किया और यह दिखाया कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है।

गहन दार्शनिक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और व्यक्तिगत अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने वाले नेता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नैतिकता उनके प्रकाशनों 'राष्ट्र धर्म', 'पंचजन्य' और 'स्वदेश' में अच्छी तरह से परिलक्षित होती थी। 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता के रूप में, उन्होंने आदर्शवाद से ओतप्रोत समर्पित कार्यकर्ताओं का एक दल खड़ा किया और संगठन का सम्पूर्ण वैचारिक ढाँचा प्रदान किया। एकात्म मानववाद का उनका दर्शन, जो भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामूहिकता का एक संश्लेषण है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है।

## 'अंत्योदय' का आदर्श

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 'अंत्योदय' दर्शन का प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ है 'अंतिम व्यक्ति का उदय'। उन्होंने देश को अत्यधिक गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए 'अंत्योदय' पर जोर दिया। यह श्री उपाध्याय के राजनीतिक और आर्थिक विचारों का मूल सिद्धांत है। दीनदयाल जी ने अपनी आर्थिक नीति में हमेशा गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण पर जोर दिया। समाज का अंतिम व्यक्ति उनके आर्थिक विचारों के केंद्र में था। उन्होंने कहा, "आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी तक पहुँचें हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज के सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा।" उनका विचार था कि राज्य को सभी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए।

## 'एकात्म मानववाद' का आदर्श

उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन को प्रतिपादित किया जो प्रत्यक्ष अलगाव में एकीकरण के धागों की खोज करता है। यह समाज और प्रकृति के साथ व्यक्तियों के एकीकरण का विचार है और इस प्रकार यह संघर्ष और पूर्वाग्रह से मुक्ति देता है। उनके अनुसार, भारतीय परम्परा व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच अलगाव को खारिज करती है और अचेतन और चेतन दोनों के साथ अपना सम्बंध स्थापित करती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ है। यह दुनिया कोई पराया स्थान नहीं है, यह पृथ्वी एक परिवार है जो हमें अलगाव और द्वंद्वात्मक सम्बंधों के विचारों से मुक्त करती है।

एकात्म मानववाद ने नस्ल, रंग, जाति या धर्म के आधार पर आंतरिक विविधता को खारिज कर दिया, इसने सभी मनुष्यों को एक जैविक हिस्से के रूप में पहचाना और राष्ट्रीय विचारों की एक आम चेतना साझा की। अन्य सभी धर्मों और सम्प्रदायों के लोग अनिवार्य रूप से एक हैं और उनकी आंतरिक एकता 'राष्ट्रीयता' की इस सामान्य चेतना पर आधारित होनी चाहिए।



# भारत की राष्ट्रनीति का विचार - एकात्म मानव दर्शन



**मुकुल कनिटकर**  
लेखक

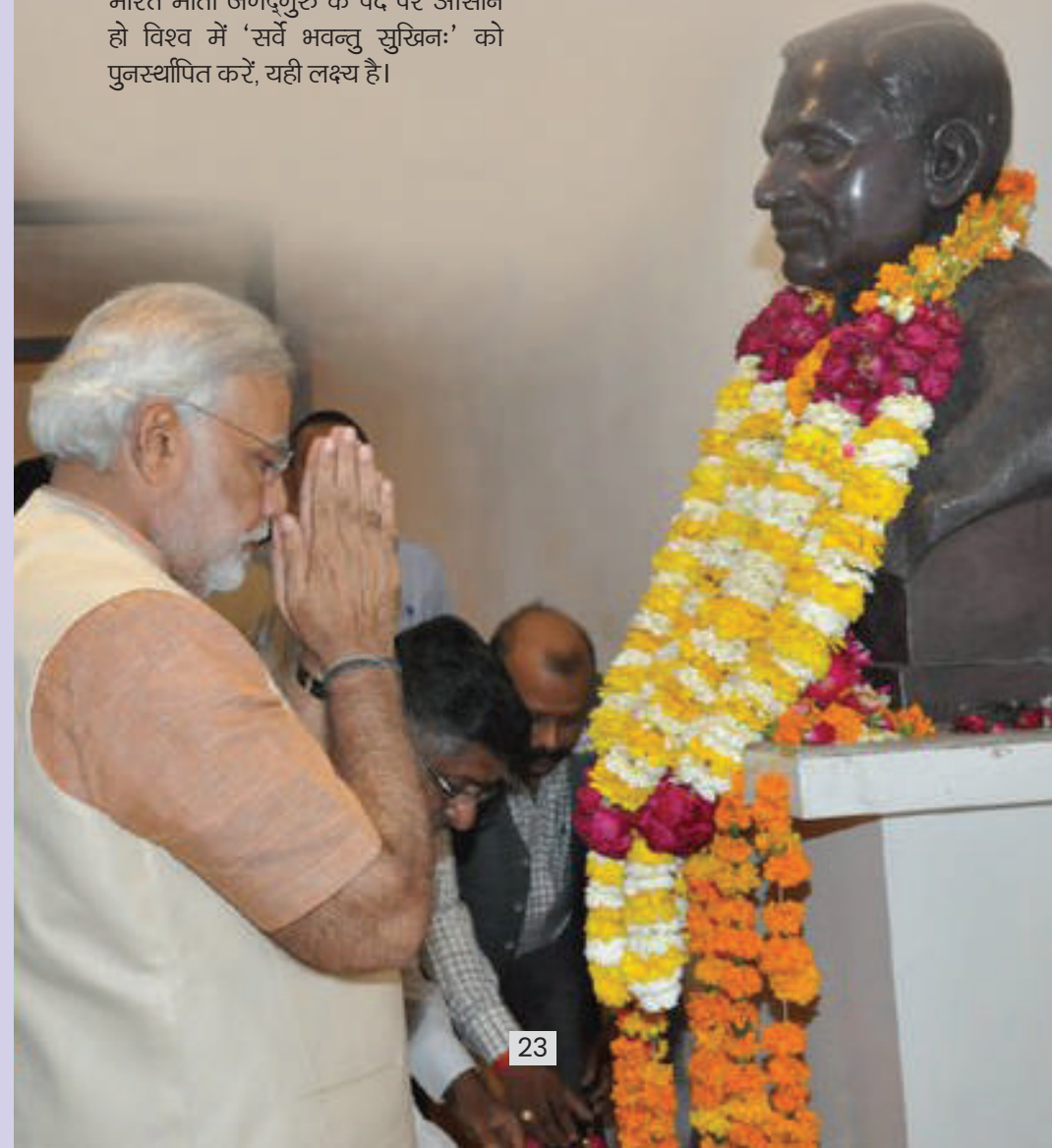
गत 'मन की बात' में प्रधानमंत्रीजी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्यायजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अंतिम व्यक्ति के विकास प्रतिमान पर चर्चा की। पंडितजी ने राजनीति से परे जाकर राष्ट्रनीति का विचार एकात्म मानव दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था। भारत के स्वत्व को समझकर उसके अनुसार सबके कल्याण हेतु सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास का यह मार्ग है। बिना प्रतिस्पर्धा के विकास का विचार राष्ट्रों के मध्य भी वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसके कारण भारत के सर्वोच्च विकसित होने से पूरी मानवता के समग्र

कल्याण का रास्ता बनेगा। एकात्मता का दर्शन कोई मर्यादित, संघर्षशील राजनीतिक अथवा आर्थिक विचारधारा नहीं है, अपितु यह सबके विकास का सर्वसमावेशक संकल्प है।

पंडितजी की जयंती 25 सितम्बर पर उन्हें स्मरण मात्र करने से एकात्म मानव दर्शन की बात प्रधानमंत्रीजी ने नहीं की, यह तो उनकी हर क्रिया में प्रदर्शित होता है। समाज और राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति के विकास हेतु चल रही योजनाओं के साथ ही सतत संवाद और सहभाग से वास्तविक लोकतंत्र का क्रियान्वयन पंडितजी के स्वप्न को साकार कर रहा है। जन-धन जैसे वित्तीय समावेश अभियान के साथ ही डिजिटल भुगतान का सर्वसुलभ उपाय स्वावलम्बी विकास को साकार कर रहा है। इसी के परिणामस्वरूप महामारी के कठिन समय में भी शासन तंत्र को संवेदनशील कर विश्व में अद्वितीय स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सामग्री वितरण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को संचालित करना भी इस अंत्योदय दर्शन का कृतिरूप ही था। स्वयं को सुरक्षित कर विश्व के आर्त देशों को आपूर्ति करने का पराक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि ही है।

भारत-केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वावलम्बन के साथ विश्व सहभाग का स्वागत करती आत्मनिर्भर अर्थनीति,

परस्पर सम्मान तथा संवाद पर आधारित आत्मविश्वासी विदेश नीति एकात्म मानव दर्शन का व्यावहारिक रूप है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख से अरुणाचल तक राष्ट्रीय एकात्मता की नीति, समर्थ, सक्षम सेना तथा अयोध्या, काशी, उज्जैन के जीर्णोद्धार आदि के द्वारा संस्कृति के साथ समृद्धि के राष्ट्रनिर्माण प्रतिमान को ही मूर्तरूप दिया जा रहा है। सर्वसमावेशी परमवैभव प्राप्त भारत माता जगद्गुरु के पद पर आसीन हो विश्व में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' को पुनर्स्थापित करें, यही लक्ष्य है।



# भारतीय सांकेतिक भाषा गौरव और पहचान का प्रतीक

“जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा सम्बल होती है - इंडियन साइन लैंग्वेज।”

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  
(‘मन की बात’ के सम्बोधन में)

“यदि हम भारत में शिक्षा की बात करें तो बधिर विद्यार्थियों के पास शिक्षा के अवसरों की कमी थी क्योंकि सांकेतिक भाषा में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इससे मूक-बधिर छात्रों को काफी परेशानी हुई, लेकिन जब से इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (ISLRTC) की स्थापना हुई है, तब से स्थिति बदल गई है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं।”

-मंजू,  
विद्यार्थी, इंडियन साइन लैंग्वेज  
रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर

श्रवण अक्षमता आज मनुष्यों में इंद्रियों की समस्याओं में सबसे आम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति एक लाख की आबादी पर 291 व्यक्ति गम्भीर और अति गम्भीर श्रवण अक्षमता से पीड़ित हैं। इनमें से एक बड़ा प्रतिशत 0-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का है।

भारत बहुत लम्बे समय से साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के लिए स्पष्ट इशारों और मानकों के अभाव का सामना करता रहा है। संवाद करने में असमर्थ, भारत की आबादी का यह हिस्सा न केवल एकांत और असंतोष की भावना से जूझता है, बल्कि विकास और समृद्धि के विभिन्न अवसरों से भी चूक जाता है।

भारत सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा का विकास करने और इसे विभिन्न क्षेत्रों में संचार के एक माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) की स्थापना की। भारतीय सांकेतिक भाषा एक बधिर-अनुकूल भाषा है। यह विजुअल-मैनुअल मोडैलिटी का उपयोग करके बनाई गई है। इसमें



अर्थ व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति इशारों की मदद से संचार करता है। पिछले सात वर्षों में ISLRTC ने लगभग 10,000 शब्दों की एक विजुअल डिक्शनरी विकसित की है।

बच्चों के लिए शिक्षा के एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण और श्रवण-बाधित विद्यार्थियों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री के विकास की सिफारिश की गई है। इसे निष्पादित करने के लिए, NCERT ने ISLRTC के साथ मिलकर 2020 में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक वीडियो पुस्तकें विकसित करना शुरू कर दिया। अब तक संगठन ने पहली से छठी कक्षा तक के लिए ई-कंटेंट शुरू किया है। वीडियो डिक्शनरी और NCERT ई-कंटेंट को ‘दीक्षा प्लेटफॉर्म’ पर एक्सेस किया जा सकता है।

भारतीय सांकेतिक भाषा सीखना

न केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सुन नहीं सकते, बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम उनके लिए एक स्वागत-योग्य समाज प्रदान करें। ISLRTC ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल के सहयोग से 23 सितम्बर, 2022 को सांकेतिक भाषा दिवस पर ‘साइन लर्न ऐप’ लॉन्च किया।

अब इनमें से कई पहलों के परिणाम सामने आने लगे हैं। हरियाणा की पूजा अपने बेटे से बात नहीं कर पा रही थीं। भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित होने के बाद माँ और बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। तिनकाजी, जिनकी छह साल की बेटी श्रवण-बाधित है, उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण लिया और अब वे आसानी से उससे बात कर सकती हैं। केरल की मंजूजी जन्म से ही सुन नहीं पाती थीं, उनके माता-पिता भी श्रवण बाधित थे। आज,

“मैं नई शिक्षा नीति 2020 में सांकेतिक भाषा को पेश करने और बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यह बधिर-समुदाय की विभिन्न पीढ़ियों के लिए परिदृश्य बदल देगा।”

-शिवम गोयल,  
विद्यार्थी, ISLRTC

भारतीय सांकेतिक भाषा पूरे परिवार के लिए संचार का माध्यम बन गई है। मंजूजी ने अब खुद एक सांकेतिक भाषा की शिक्षिका बनने का फैसला किया है। इस क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के परिणामस्वरूप हजारों ऐसी प्रेरक कहानियाँ सामने आई हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' सम्बोधन में एक और महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख किया, जिसका दृष्टिबाधित लोगों के एक बड़े वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। असमिया भाषा के सबसे पुराने शब्दकोशों में से एक हेमकोश का ब्रेल में अनुवाद किया गया था। हेमकोश

के इस संस्करण में लगभग 10,000 पृष्ठ और 1 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। इसे 15 से अधिक खंडों में प्रकाशित किया जाएगा।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के तहत काम कर रही भारत सरकार ने एक समावेशी नया भारत बनाने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्र के अमृतकाल में प्रवेश के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए ये महत्वपूर्ण परिवर्तन यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांगजन शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित न रहें, वे उस गर्व तथा पहचान से भी वंचित न हों, जिसका हर इंसान हकदार है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक भारतीय उस समग्र विकास के युग का हिस्सा बने, जिसकी ओर राष्ट्र आगे बढ़ रहा है।

भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के बारे में अधिक जानने के लिए QR कोड स्कैन करें।



A	B	C	D
E	F	G	H
I	J	K	L
M	N	O	P
Q	R	S	T
U	V	W	X
	Y	Z	

## ISL शब्दकोश को आम लोगों के लिए अधिक सुगम बनाना



वीडियो प्रारूप में 10,000 शब्द शामिल



साइन वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा सकता है



द्विभाषी ऐप, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध



एंड्राइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध

## श्रवण-बाधित भारतीयों के लिए खुले नए आयाम

'मन की बात' के 93वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के श्रवण-बाधित नागरिकों और संचार साधनों की कमी के कारण दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में उल्लेख किया। अवसरों का एक समान आधार प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (ISLRTC) की स्थापना की। आज, ISLRTC ISL को विकसित करने और बधिर छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

दूरदर्शन की टीम ने ISLRTC के छात्रों से बात की, यह जानने का प्रयास किया

कि इन पहलों से उनके सीखने के अनुभव में कैसी और क्या मदद मिली?

एक छात्र लकी शाह ने बताया कि कैसे ISLRTC की स्थापना ने श्रवण-बाधित छात्रों के लिए शैक्षिक सामग्री को आसानी से सुलभ बना दिया है। ISLRTC के एक अन्य छात्र शिवम गोयल ने कहा, "पहले अधिकांश आबादी उस सांकेतिक भाषा को नहीं समझती थी, जिसे बधिर इस्तेमाल करते थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारी अपनी अलग संस्कृति है। इस स्थिति ने हमारे लिए बहुत सारी बाधाएँ खड़ी कर दीं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में भारतीय



सांकेतिक भाषा को बढ़ावा दिया है, परिदृश्य बदल रहा है। यह प्रगतिशील कदम उठाने के लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ।"

छात्रा कविता ने उन चुनौतियों के बारे में बात की, जिनका सामना पहले बधिर समुदाय ने किया था और कैसे ISLRTC इसे दूर करने में मदद कर रहा है। "पहले, श्रवण-बाधित छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि अधिकांश स्कूल और कॉलेज मौखिक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते थे। अन्य संस्थान और संगठन जैसे पुलिस स्टेशन, अस्पताल, बैंक, कोर्ट भी हमारे लिए दुर्गम थे, क्योंकि संचार का कोई उचित तरीका नहीं था, लेकिन ISLRTC की स्थापना के बाद बधिरों के अनुकूल भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ रही

## भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के उद्देश्य:



भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) में शिक्षण और अनुसंधान के संचालन के लिए जनशक्ति विकसित करना



प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर बधिर छात्रों के लिए शैक्षिक साधन के रूप में आईएसएल के उपयोग को बढ़ावा देना



भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना



ISL भाषाई रिकॉर्ड बनाना, ISL का विश्लेषण करना और ISL शब्दावली बनाना

ISL को समझने और उपयोग करने के लिए विभिन्न हितधारकों को उन्मुख और प्रशिक्षित करना

ISL को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए बधिरों के संगठनों के साथ सहयोग करना

आईएसएल को और बेहतर करने के लिए दुनिया के अन्य हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी एकत्र करना



है। अब गैर-बधिर लोग भी अपने ISL कौशल का विकास कर रहे हैं। नतीजा यह है कि संचार हमारे लिए आसान होता जा रहा है। ISLRTC ने पिछले 7 सालों में हमें बहुत कुछ दिया है। आज, ISLRTC डिव्शनरी, ISLRTC और ISL में विभिन्न कहानी पुस्तकें और विभिन्न प्रशिक्षण सत्र समुदाय को एक पहचान बनाने में मदद कर रहे हैं।"

भारत को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए राष्ट्र को प्रत्येक नागरिक के योगदान की आवश्यकता है। आज भारतीय सांकेतिक भाषा के विकास ने देश के श्रवण-बाधित लोगों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो संचार की इस सुबह के साथ भारत के श्रवण-बाधित नागरिक कंधे-से-कंधा मिलाकर चल सकेंगे।

# ISL : समावेशी संचार का ध्वजवाहक



**राजेश यादव**

निदेशक, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र

ISL के माध्यम से बधिर व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बधिर संघों ने ISL के विकास और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट संस्थान स्थापित करने की माँग रखी थी। भारत में बधिर लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 28 सितम्बर, 2015 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के तत्वावधान में इंडियन साइन्स लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर नामक एक स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी। इस केंद्र का प्रमुख लक्ष्य भारतीय सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल, अध्यापन और उसमें शोध के लिए लोगों को तैयार करना है। इसके लिए केंद्र दो वर्ष की अवधि वाले दो डिप्लोमा कोर्स कराता है, जिन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से मंजूरी प्राप्त है। डिप्लोमा के नाम हैं- डिप्लोमा इन इंडियन साइन्स लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन्स लैंग्वेज।

ISL के बारे में बताने और उसके इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के बारे में ISLRTC उनकी स्थापना के बाद से ही श्रम कर रही है। ISLRTC की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के संदर्भ में दूरदर्शन को ISL सेवाएँ प्रदान करता है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 26,810,557 मूक-बधिर व्यक्तियों में से 50,71,007 बधिर हैं और 19,98,535 बोलने में अक्षमता से जूझ रहे हैं। सांकेतिक भाषाओं में हाथों, चेहरे के भावों और सिर/शरीर की भंगिमाओं के माध्यम से दृश्य-सांकेतिक तरीके से संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है। सुनने में अक्षम लोगों के लिए सांकेतिक भाषाएँ सम्प्रेषण का प्रमुख माध्यम होती हैं। बधिर समुदाय देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है।

सम्प्रेषण को सरल बनाने और मूक एवं बधिर लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु ISLRTC ने 10,000 शब्दों वाली इंडियन साइन्स लैंग्वेज डिक्शनरी तैयार की है, जो देश में ISL का सबसे बड़ा शब्दकोष है। ISL के शब्दकोश को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए ISL डिक्शनरी ऐप को एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन में भी विकसित किया गया है।

बधिर बच्चों को आसानी से सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री को ISL में डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए ISLRTC ने NCERT के साथ MoU साइन किया है। कक्षा 1-5 तक की NCERT की पाठ्य पुस्तकें ISL में गत वर्ष जारी की गई थीं। कक्षा 6 की NCERT पाठ्यपुस्तक ISL में 23 सितंबर, 2022 को सांकेतिक भाषा दिवस पर लॉन्च की गई थी।

बधिरों के लिए केंद्र ने ISL में 99 एक्सेसिबल वीडियोज़ विकसित कराए हैं, ताकि उन्हें MHA, MoHFW, PIB और DEPwD द्वारा कोविड-19 महामारी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना, दिशानिर्देश

और जागरूकता से जुड़ी सामग्री प्राप्त हो सके।

'भारतीय सांकेतिक भाषा - एक राष्ट्र, एक सांकेतिक भाषा' विषय पर ISLRTC ने 72वें गणतंत्र दिवस पर एक झाँकी के जरिए सहभागिता की थी। झाँकी का लक्ष्य ISL को प्रोत्साहन देकर बधिर लोगों के लिए बाधारहित वातावरण तैयार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और उसके प्रति जागरूकता फैलाना था।

केंद्र ने DMRC के साथ एक MoU साइन कर DMRC के फ्रंटलाइन स्टाफ सदस्यों के लिए बुनियादी और आवश्यकता-आधारित ISL संचार ट्रेनिंग का संचालन किया है। अभी तक DMRC के 978 कर्मचारियों को बुनियादी ISL का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बधिर छात्रों को उनके रचनात्मक हुनर को विकसित करने के लिए केंद्र प्रत्येक वर्ष भारतीय सांकेतिक लिपि प्रतियोगिता का आयोजन करता है।



# ISL के साथ समावेशन स्वप्न नहीं, बल्कि वास्तविकता



**टी.के.एम. संदीप**

सीईओ, डेफ़ इनेबल्ड फ़ाउंडेशन

देश में बधिर लोग कई चुनौतियों का सामना करते रहे हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से दूर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि सरकार और प्रबुद्ध समाज; दोनों दिव्यांगों के विकास के लिए अभिनव और संरचित समाधान ला रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) और डेफ़ इनेबल्ड फ़ाउंडेशन (डीईएफ़) जैसे संगठनों की स्थापना के साथ देश में बधिरों के अनुकूल वातावरण बन रहा है।

'श्रवण अक्षमता एक दायित्व नहीं है। सांकेतिक भाषा सिर्फ बधिरों की भाषा नहीं है।' यही शब्द डीईएफ़ की स्थापना का आधार बन गए। एक ऐसा संगठन, जिसकी स्थापना मेरे जैसे बधिर व्यक्ति ने की, जिसे कभी एक गैर-बधिर की तुलना में हीन माना जाता था। मैंने एक ऐसा संस्थान खोलने के एजेंडे के साथ डीईएफ़ की शुरुआत की, जो बधिर युवाओं को

खुद को शिक्षित करने, अच्छी नौकरी खोजने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि वे किसी भी प्रकार की सहायता या सहानुभूति के बिना स्वतंत्र रूप से सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। मुझे नहीं पता था कि एक सरल सा यह विचार एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

हमारी शिक्षा प्रणाली ने परम्परागत रूप से, शिक्षण के मौखिक रूप की हिमायत की, लेकिन बधिर विद्यार्थियों की सहायता के लिए दुभाषिण शायद ही उपलब्ध थे। इसके अलावा विशेष शिक्षा संस्थान केवल चुनिंदा महानगरीय शहरों में ही थे। बुनियादी ढाँचे के मुद्दों के अलावा, एक बधिर व्यक्ति को सोशल स्टिग्मा से निपटना पड़ता था, जो बहरेपन को कर्म और धर्म के चश्मे से देखते थे। इतना ही नहीं, कई बधिर बच्चों के माता-पिता ने भी उनकी जरूरतों को समझने की बजाय उन्हें नियमित गैर-बधिर स्कूलों और कॉलेजों में भेजा, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती संचार की खाई थी, जो समाज के भीतर व्यापक रूप से व्याप्त थी।

चूँकि चुनौतियाँ बहुत बड़ी थीं, इसलिए प्रयास भी उसी स्तर के करने की आवश्यकता थी और वह भी हर तरफ से। ऐसे वातावरण का निर्माण करना महत्वपूर्ण था, जो न केवल उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करे, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में भी शामिल करे। भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और

अनुसंधान केंद्र (ISLRTC) जैसी पहल के साथ सरकार ने एक बड़ी छलाँग लगाई है। यहाँ तक कि डीईएफ़ भी इसी दर्शन पर काम करता है। यह बधिर विद्यार्थियों के लिए काम सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए न केवल अकादमिक सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है, बल्कि बधिरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा, कार्य और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में सांकेतिक भाषा कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।

एक अन्य प्रमुख पहल, जिसका शिक्षा और आर्थिक अवसरों के मामले में बधिरों को मुख्यधारा में लाने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, वह है भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) डिक्शनरी। हमने ISL डिक्शनरी बनाने में सरकार के साथ-साथ प्रबुद्ध समाज के असाधारण प्रयासों को देखा है। ISLRTC, अपनी ISL डिक्शनरी के अभी तक तीन संस्करण लेकर आया है। वास्तव में हमने 2018 में डीईएफ़ ISL मोबाइल डिक्शनरी लॉन्च की थी ताकि बड़ी संख्या में लोगों तक संकेत भाषा के ज्ञान का प्रसार किया जा सके। आज, हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 60,000 से अधिक अंग्रेजी शब्दों का भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया है और इस ऐप के न केवल भारत, बल्कि बाँग्लादेश, अमरीका,

ब्रिटेन और तुर्की जैसे देशों के 1,98,000 से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

जब केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से स्कूलों में भारतीय सांकेतिक भाषा शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की, तो हम रोमांचित थे कि हमारे देश ने आखिरकार लोगों को एक साथ लाने में भारतीय सांकेतिक भाषा के महत्व को पहचानना शुरू कर दिया है। इस विचार ने, कि किसी दिन लोगों को खुद को व्यक्त करने के लिए दुभाषिण की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, मुझे आश्चर्य किया कि भारतीय बधिर समुदाय का भविष्य आखिरकार दिन-पर-दिन बेहतर और उज्वल दिख रहा है। यह एक नए सवेरे की शुरुआत है, जिसमें समावेशन को अब दूर का सपना नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह एक वास्तविकता होगी, जो धीरे-धीरे साकार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध है कि भारतीय सांकेतिक भाषा को इस देश की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए, जिससे इस देश के बधिरों की संस्कृति को मान-महता मिले।

श्रवण-बाधित नागरिकों हेतु सरकार के पहलों पर श्री टी.के.एम.संदीप के विचार जानने के लिए QR कोड स्कैन करें।



# स्वच्छ भारत

## हर भारतीय का संकल्प

“हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, मरीन ईको-सिस्टम्स के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है तो दूसरी ओर हमारे बीचेज पर फ़ैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गम्भीर और निरंतर प्रयास करें।”

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  
(‘मन की बात’ के सम्बोधन में)

“जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, तब से हमारे सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों में जिम्मेदारी की एक नई भावना पैदा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को जिस तरह का सामाजिक प्रभाव दिया गया है, वह अभूतपूर्व है।”

—तेजस्वी सूर्या  
सांसद और अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्म  
दर्शनयोग्यत्वानि च ॥

शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन का प्रफुल्ल भाव, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों पर जीत और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है।

वैदिक काल में तन, मन और आत्मा की स्वच्छता सर्वोपरि थी। प्राचीन काल में ऋषियों का मानना था कि स्वच्छ परिवेश और स्वस्थ शरीर के बिना पूजा और ध्यान बेहद कठिन है। स्वच्छता के पैरोकार महात्मा गाँधी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर उसे आजादी के स्वप्न से जोड़ा। आज भी नए भारत (न्यू इंडिया) के उदय के साथ इन मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के रूप में देखा जा रहा है।

प्राचीन काल से ही माना गया था कि स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ जल और ताज़ी हवा के लिए, स्वस्थ एवं स्वच्छ विधियों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना ज़रूरी है।

हालाँकि स्वच्छता की जिम्मेदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कई दशकों से मानव की उपेक्षा के कारण अपशिष्ट संचय और पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है। नतीजतन, जल, थल और वायु पर इसका दुष्प्रभाव, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए

माइक्रोप्लास्टिक, मिट्टी और गहरे महासागर में ही नहीं, मानव रक्त तक में पाए गए हैं। समुद्री सतह पर प्लास्टिक की बढ़ती उपस्थिति, खाद्य शृंखला पर बुरा असर डाल रही है, जिससे जल जीवों के स्वास्थ्य को लेकर अधिक गम्भीर समस्याएँ पैदा हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिशा में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता महसूस की और एकजुट राष्ट्र के रूप में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए एक साफ़-सुथरे भारत का निर्माण करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आरम्भ किया। उन्होंने हर एक जगह को साफ़-सुथरा बनाने के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने में हर एक नागरिक का साथ माँगा। प्रचार-वाक्य ‘एक क़दम स्वच्छता की ओर’ के साथ, भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान आरम्भ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के मूल व्यवहार में बदलाव आया है।

अभियान ने बड़ी सफलता हासिल

की, हालाँकि, देश यहीं थमा नहीं। लोगों ने स्वच्छता का महत्व समझा और देश को व्यक्तियों, नागरिक-समाज, युवा संगठनों और सरकार के अनगिनत प्रयास देखने को मिले। नदियों, सागर-तटों, जल निकायों आदि की सफाई जैसी हर स्तर पर लोगों ने छोटी ही नहीं, बड़ी पहल भी की, जो स्वच्छ और हरित नए भारत के निर्माण में हर भारतीय को जोड़ रही हैं।

स्वच्छता का लोकाचार आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प का दोहरा उद्देश्य पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम सहित विभिन्न पहल की हैं। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ और क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन कार्यक्रम; ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मिशन, जिसका उद्देश्य कचरे की पहचान करना, उसे विकसित करना और प्रौद्योगिकी की मदद से पदार्थों को पुनर्विक्रित करके उनमें से ज़रूरी संसाधन निकाल कर ऊर्जा तैयार करना तथा प्लास्टिक कचरा



निपटान के पर्यावरण-अनुकूल समाधान स्थापित करने के लिए उन एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर उल्लेखनीय प्रतिबंध लगाना, जिनकी पहचान की जा चुकी है।

इन पहलों के साथ ही देश में जन-भागीदारी की ज़बरदस्त भावना देखी गई है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आए और स्वच्छता के इस सामूहिक आंदोलन में शामिल हुए। स्वच्छ भारत के लिए शुरू किया गया सरकार का स्वच्छता अभियान, लाखों भारतीयों के प्रयासों से 'जन आंदोलन' में बदल चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल के 'मन की बात' सम्बोधन में, 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' अभियान का उल्लेख किया, जिसके तहत 75 दिन में 75 सागर तटों पर नागरिकों ने सामूहिक सफाई अभियान चला कर समुद्रों की सेहत सुधारने में योगदान किया। तटीय स्वच्छता अभियान में समुद्र से कम से

“मेरठ नगर के व्यस्ततम चौराहों, पार्कों आदि में निष्प्रयोज्य सामग्री का प्रयोग करते हुए जनता के दैनिक उपयोगार्थ एवं दर्शनार्थ कई वस्तुएँ, कलात्मक संरचनाएँ मेरठ नगर निगम द्वारा स्थापित कराई गईं। इन संरचनाओं का स्थानीय जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और अनुपयोगी वस्तुओं पर अल्प व्यय से कलात्मक अभिनव प्रयोगों के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हुई।”

-ए के शर्मा

मंत्री, ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग, उ.प्र.

कम 1,500 टन कचरा हटाने का लक्ष्य रखा गया था।

अभियान में सक्रिय भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने वाली लोगों द्वारा संचालित पहल और सामुदायिक गतिविधियाँ, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। चाहे वह बेंगलुरु की 'यूथ फ़ॉर परिवर्तन' टीम हो, जिसका बड़ा ही स्पष्ट आदर्श वाक्य है- 'स्टॉप कम्प्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग' या पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से मेरठ का 'कबाड़ से जुगाड़' अभियान ऐसे हैं, जो सरकार की अगुआई में जारी पहलों के साथ जन-भागीदारी से जुड़ कर इसे वास्तव में जन-आंदोलन का रूप दे रहे हैं और स्वच्छ भारत का सपना सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं।

आज जब राष्ट्र अमृत काल में प्रवेश कर रहा है तो लोगों के सामूहिक प्रयासों और परिवर्तन की अटूट भावना के साथ-साथ सरकार, समुदाय और, सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत स्तर पर केंद्रित पहलों के माध्यम से ही स्वच्छ नए भारत का निर्माण हो रहा है।

## 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर'

प्रधानमंत्री के स्वच्छता के आह्वान के तहत व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लक्षित करने के लिए रणनीतिक अंतर्निहित लक्ष्यों के साथ 5 जुलाई, 2022 को 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' अभियान शुरू किया गया था। हमारे समुद्रों और समुद्र तटों की सुरक्षा और सफाई के लिए जनांदोलन के माध्यम से 75 दिनों का यह अभियान शुरू किया गया था। देश भर के 75 समुद्र तटों पर 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' अभियान चलाया गया, जिसमें समुद्र तट के प्रत्येक किलोमीटर के लिए 75 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अभियान का समापन 17 सितम्बर, 2022 (अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस) पर सबसे बड़े समुद्र तट सफाई कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें भारत के 7500+ किमी. समुद्र तट के 75 समुद्र तटों को शामिल किया गया था।

इस आयोजन का केंद्र गोवा रहा, जहाँ स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम हुए। राज्य में 17 सितम्बर को सभी 35 समुद्र तटों

पर तटीय सफाई अभियान मनाया गया, जिसका उद्घाटन मीरामार समुद्र तट पर किया गया। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लम्बे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान था, जिसमें सबसे अधिक लोगों ने भाग लिया था।

हमारी दूरदर्शन टीम ने स्वच्छता अभियान के बारे में पणजी के उप महापौर श्री संजीव नाइक से बात की।

श्री नाइक ने हमें बताया कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के जन्मदिन के अवसर पर हमने मीरामार समुद्र तट पर एक समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी भाग लिया था। पणजी के मंत्रियों और विधायकों के साथ गोवा के छात्रों और सरकारी विभागों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सफाई अभियान में भाग लिया और यह अभियान बहुत सफल रहा। हमने समुद्र तट के किनारे एक ह्यूमन चेन बनाई थी, जिसकी सराहना पूरे देश में की गई।”



## स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर



स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर  
Clean Coast Safe Sea

- 3 जुलाई, 2022 को शुरू किया गया और 17 सितंबर, 2022 को "अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस" पर समापन हुआ
- व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से लक्ष्य परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य
- समुद्री कूड़े को कम करने, प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग, स्रोत पर पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य
- अभियान के 3 लक्ष्य हैं—ज़िम्मेदारी से उपभोग करना, घर पर कचरे को अलग करना और सही तरीके से कचरे का निपटान करना
- अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए "इको मित्रम" ऐप लॉन्च किया

75 दिन समुद्र तट स्वयंसेवक/किमी 00+ किमी कोस्टलाइन

# व्यवहार परिवर्तन और सार्वजनिक स्वच्छता की जिम्मेदारी का नया दौर



**तेजस्वी सूर्या**

सांसद और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष

*हमारी दूरदर्शन टीम ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बारे में तेजस्वी सूर्या से बात की।*

जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, तब से हमारे सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों में जिम्मेदारी की एक नई भावना पैदा हुई है। प्रधानमंत्री मोदीजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब वे किसी मुद्दा या योजना का प्रचार करते हैं तो वे जनभागीदारी की भावना को सुनिश्चित करते हैं। शायद, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने विकास को एक जन आंदोलन बनाया है। इसलिए आज हम स्वच्छ भारत अभियान को केवल एक सरकारी पहल के रूप में नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में देख रहे हैं।

स्कूली बच्चे, खासकर प्राइमरी स्कूल

के बच्चे, इस स्वच्छ भारत अभियान के सिपाही हैं। अगर उनके माता-पिता या घर के बुजुर्ग अपने घरों के बाहर कूड़ा डालते हैं, तो वे ही तुरंत उन्हें बताते हैं कि यह गलत है, तो यह सांस्कृतिक परिवर्तन, यह व्यवहार परिवर्तन कुछ ऐसा है, जिसे हम पहली बार देख रहे हैं। जब हम दूसरे देशों का दौरा करते हैं, तो हम अपने आस-पास की सफाई से चकित होते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और हम फिर से कूड़ा-कचरा करने लगते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने वास्तव में इसे बदल दिया है, लोग आज महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारी सड़कों को साफ रखना है, तो हमें कूड़ा नहीं फैलाना है। अगर हमारे सार्वजनिक शौचालय साफ-सुथरे होने चाहिए, तो हमें ही उनका अच्छी तरह से रखरखाव करना है। अगर हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म को साफ रखना है तो हमें धूकना नहीं है। भारत में सार्वजनिक स्थानों की सफाई अब केवल सरकार का कर्तव्य नहीं रही, यह सभी भारतीयों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसका श्रेय प्रधानमंत्रीजी को जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान एक एकीकृत अभियान रहा है, क्योंकि इसका शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, अभियान का एक बड़ा सामाजिक प्रभाव है, क्योंकि इस योजना के तहत बनाए गए कुछ करोड़ शौचालयों ने सही मायने में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है। 21वीं सदी के भारत में यह अविश्वसनीय था कि



जब तक प्रधानमंत्री ने इस अभियान को शुरू नहीं किया, तब तक भारत में करोड़ों महिलाएँ खुले में शौच कर रही थीं और एक राष्ट्र के रूप में हमने इसे इतने दशकों तक होने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जिस तरह का सामाजिक प्रभाव दिया गया है, वह अभूतपूर्व है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अरब भारतीयों को सामूहिक रूप से इस देश के निर्माण और इसे अभूतपूर्व ऊँचाइयों पर ले जाने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान एक बार की गतिविधि नहीं है, यह एक सतत कार्यक्रम है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम की सफलता को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैमाना इस पहल द्वारा लाए गए सांस्कृतिक परिवर्तन का आकलन करना होगा। जैसा कि मुझे याद है, यूपी में एक महिला थी, जिन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया था, क्योंकि जिस घर में उनकी

शादी हो रही थी, उस घर में शौचालय नहीं था। एक स्कूल जाने वाली लड़की ने अपने स्कूल में एक साफ शौचालय की माँग की, क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं था, ये सभी देश में सांस्कृतिक और व्यवहार परिवर्तन के उदाहरण हैं।

मुझे लगता है कि हम सार्वजनिक शिक्षा के एक महान स्तर पर पहुँच रहे हैं। जितने अधिक युवाओं को इस अभियान के बारे में जागरूक किया जाएगा और इस बात से अवगत कराया जाएगा कि सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, तब हम उस स्तर की स्वच्छता को बनाए रखने में सक्षम होंगे, जो हम विदेशों में देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जन आंदोलन है, जो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सामूहिक रूप से नागरिकों की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान पर युवा आइकन श्री तेजस्वी सूर्या के विचार जानने के लिए QR कोड स्कैन करें।



## मेरठ नगर निगम का 'कबाड़ से जुगाड़'

मेरठ नगर निगम द्वारा की गई पहल 'कबाड़ से जुगाड़' से चौराहों और पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है। इस पहल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में सराहना की, जिससे नगर निगम की पूरी टीम का उत्साह बढ़ा।

*हमारी दूरदर्शन टीम ने मेरठ नगर के निवासियों और निगम के हितधारकों से बातचीत की।*

**पूजा रावत**, मेरठ निवासी का कहना है, "पहले जब हम रात को घूमने निकलते थे तो सिर्फ शहर की गंदगी नज़र आती थी, पर अब जो वेस्ट सामान सड़कों के किनारे फेंक दिए जाते थे, उनको रियूज करके मेरठ नगर निगम के अधिकारियों ने शहर को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब एक नया मेरठ देखने को मिलता है और शहर की सुंदरता देखकर



हमारा मन खुश हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है कि नगर निगम के कार्य की गूँज प्रधानमंत्रीजी तक पहुँची।"

**अमित पाल**, नगर निगम आयुक्त, ने बताया, "जब शासन द्वारा सिंगल-यूज प्लास्टिक को बैन किया गया, उस समय नगर निगम मेरठ में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुलाकर वार्ता की गई कि किस तरह से इस अभियान को और भी इफेक्टिव बनाया जा सके। उस समय ये बात निकल के आई कि जो भी स्क्रेप या कबाड़ हमारे सैनिटेशन स्टोर में पड़ा है, क्यों न उसको सिटी ब्यूटिफिकेशन कार्य से जोड़ा जाए। स्टोर में पड़े पुराने टायर, इम, प्लास्टिक स्क्रेप, लोहे आदि के कबाड़ के सामान से हमारे शहर के चौराहों में इनसे बनाई आकृतियाँ इनस्टॉल की गईं। मेरठ नगरवासियों द्वारा इस अभियान की काफ़ी सराहना की गई।"

भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के तहत 'इंडियन स्वच्छता लीग' अवार्ड में मेरठ नगर निगम को चयनित किया गया, साथ ही पूरे प्रदेश में दूसरा नम्बर और पूरे देश में 15वाँ स्थान प्राप्त करने के लिए, 'फॉस्टेस्ट मूवर सिटी' अवार्ड्स में भी मेरठ नगर निगम को चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में अपने



कार्यक्रम की सराहना सुनते हुए अमित ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा, "मेरठ नगर निगम प्रधानमंत्रीजी की मंशा अनुसार इस कार्यक्रम को और आगे ले जाते हुए सिटी ब्यूटिफिकेशन के काम को जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ाएगा।"

**इंद्र विजय सिंह**, सहायक नगर आयुक्त ने भी अपना अनुभव साझा किया, "निगम के कबाड़ को हमने एक वेंडर हायर करके उनको दिया और डिजाइन बताकर अलग-अलग चीज़ें बनवाईं, जिनका इस्तेमाल चौराहों और सड़क किनारे किया गया। तीन 'R' प्रिंसिपल यानी 'रिड्यूस, रियूज और रिसायकल' का इस्तेमाल करते हुआ हमने अभी चिल्ड्रेस पार्क में एक गाँधीजी की स्मृति बनाई है। इसमें टेले, उनकी चेन, फ्री व्हील का इस्तेमाल करके चरखा बनाया गया है, जो काफ़ी दर्शनीय है और एक सेल्फी पॉइंट के रूप में मशहूर हो रहा है। हम प्रधानमंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमने जो भी काम किया, उसकी उन्होंने तारीफ़ की।"

मेरठ के रहने वाले **यश** का कहना है, "जिस तरीके से 'कबाड़ से जुगाड़' से हमारे शहर को इतना सुंदर और स्वच्छ



बनाया गया है, यह बात बहुत ही सराहनीय है। मैं नगर निगम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नया और इनोवेटिव आइडिया निकाला, जहाँ लोग इन सब चीज़ों को फ़ेंक देते थे, अब नगर निगम की इस पहल से वही कबाड़ नए रूप में इस शहर की सुंदरता बढ़ा रहा है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं सभी से यह आग्रह करूँगा कि इस मुहिम में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएँ। प्रधानमंत्रीजी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे शहर की इस मुहिम की तारीफ़ की।"

नागरिक **रिया जावला** ने भी अपने विचार व्यक्त किए, "इस प्रोजेक्ट में हमने देखा है कि नगर निगम द्वारा सभी चौराहों को रिसायकल्ड कबाड़ से सुंदर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के जिक्र के बाद यह उम्मीद है कि इस शहर का हर इंसान इस पहल को बढ़ावा देगा और हम सब मिलकर मेरठ शहर को सुंदर बनाने में कामयाब होंगे।"

'कबाड़ से जुगाड़' पर विशेष रिपोर्ट देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



## 'कबाड़ से जुगाड़' : निष्प्रयोज्य सामग्री का उपयुक्त प्रयोग



**ए.के. शर्मा**

मंत्री, ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग, उ. प्र.

'कबाड़ से जुगाड़' एक ऐसा अभियान है, जिसमें अपशिष्ट और निष्प्रयोज्य पदार्थों एवं वस्तुओं से पर्यावरण संरक्षण, नगरीय सौंदर्यीकरण तथा जन-उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत कम खर्च में कलात्मक और आकर्षक संरचनाओं का निर्माण किया जाता है।

स्वच्छता अभियान के दौरान मेरठ नगर निगम द्वारा उनके विभिन्न विभागों में उपलब्ध अनुपयोगी वस्तुएँ, जैसे आयरन स्ट्रैप, पुराने निष्प्रयोज्य टायर, तेल के पुराने ड्रम, रिक्शों के पहिए आदि का प्रयोग करते हुए सुंदर एवं दर्शनीय संरचनाओं और कलाकृतियों के निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। इसके अंतर्गत मेरठ नगर के व्यस्ततम चौराहों, पार्कों आदि में निष्प्रयोज्य सामग्री का प्रयोग करते हुए जनता के दैनिक

उपयोगार्थ एवं दर्शनार्थ कई वस्तुएँ, कलात्मक संरचनाएँ मेरठ नगर निगम द्वारा स्थापित कराई गईं। नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित इन संरचनाओं का स्थानीय जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और अनुपयोगी वस्तुओं से अल्प व्यय पर कलात्मक अभिनव प्रयोगों के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हुई। प्रधानमंत्रीजी ने मेरठ नगर में निगम द्वारा 'कबाड़ से जुगाड़' अभियान के अंतर्गत की गई पहल को अपने 'मन की बात' में स्थान देकर इस प्रयास में जुड़े हुए सबका बहुत उत्साहवर्धन किया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के निवासी और सरकार प्रधानमंत्रीजी को सादर धन्यवाद देते हैं।

मेरठ नगर निगम स्वास्थ्य स्टोर में उपलब्ध निष्प्रयोज्य पुराने रिक्शा टेलों के फ्री व्हील, साइकिल चेन, आयरन स्ट्रैप आदि को प्रयोग करते हुए अत्यधिक न्यूनतम व्यय पर गाँधी आश्रम चौराहे के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ मिनी फाउंटेन स्थापित किया गया। नगर निगम द्वारा वाहनों के पुराने निष्प्रयोज्य टायरों का प्रयोग करते हुए चयनित पार्कों में वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं की सुविधा के दृष्टिगत बैठने हेतु प्रथमतः स्टूलों तथा मेजों के 15 सेट का निर्माण कार्य कराया गया है।

वाहनों में प्रयुक्त होने वाले इंजन आयल के निष्प्रयोज्य ड्रम का प्रयोग करते हुए ड्रम पर पेंटिंग, ब्यूटीफिकेशन आदि का कार्य कराते हुए पौधारोपण हेतु स्ट्रीट



इंस्टॉलेशन का निर्माण कराया गया है। जिन स्थानों पर पौधारोपण हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं थे, उन सभी स्थानों पर पुनर्निर्मित ड्रम को कलात्मक गमलों की तरह स्थापित किया गया है। इससे मार्ग के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ नागरिकों में 3R प्रिंसिपल की जागरूकता भी बढ़ रही है।

पुराने जे.सी.बी./ट्रैक्टर व टेलों के टायरों और रिमों से डिस्पले वॉल तथा बैरिकेडिंग तथा आइरन स्ट्रैप से लाइट ट्री का निर्माण कराया गया है। निष्प्रयोज्य टायरों से बच्चों के खेलने हेतु झूले, प्ले टनल, पौधारोपण हेतु क्रीपर्स आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा मेरठ नगर निगम द्वारा प्रतिदिन इकट्ठा की जाने वाली प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए पॉलीथिन रिसाइकलर्स के साथ अनुबंध किया गया है। इनके माध्यम से पार्कों में वॉकिंग ट्रैक्स, बैंच, वॉल म्यूरल्स का निर्माण कराया जा रहा है। मेरठ नगर के महत्वपूर्ण चौराहे 'बच्चा पार्क' के निकट फ्री व्हील, पुरानी रिक्शा चेन आदि के प्रयोग से महात्मा गाँधी का चित्र उकेरा गया है। नगर के एक अन्य व्यस्त चौराहे 'जेल-चुंगी' पर बीचों-बीच कई चरखों की आकर्षक संरचना बनाई

गई है, जिसमें कबाड़ का प्रयोग किया गया है।

पुराने पहियों को अलग-अलग रंगों में रंग कर संतुलित अनुपात में व्यवस्थित करते हुए नगर के वेस्टर्न कचहरी मार्ग पर डिवाइडर के रूप में भव्यता के साथ संयोजित किया गया है।

नगर निगम द्वारा विगत दो-तीन माह में पर्यावरण के दृष्टिगत जन-जागरूकता हेतु इस प्रकार के कराए गए कार्य एवं इस दिशा में विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों के सामंजस्य से आम जनमानस में विभिन्न निष्प्रयोज्य सामग्री को पुनः प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।

पर्यावरण की सुरक्षा और अनुपयोगी वस्तुओं से बिना विशेष खर्च के समाज के लिए उपयोगी आर्थिक परिसम्पत्ति के निर्माण की दृष्टि से यह प्रयोग बहुत ही सराहनीय है। इसमें प्रधानमंत्रीजी का आशीर्वाद मिलने के कारण यह स्थानीय मुहिम अब एक राष्ट्रीय मुहिम बन जाएगी, इसमें संदेह नहीं। प्रधानमंत्रीजी को उनके उद्बोधन में प्रदेश के नगर मेरठ की 'कबाड़ से जुगाड़' के लिए की गई प्रशंसा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पुनः सादर धन्यवाद।



**अमित अमरनाथ**

संस्थापक, यूथ फ़ॉर परिवर्तन

## 'स्टॉप कम्प्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग'

देश परिवर्तन में युवाओं की अहम भूमिका पर **अमित अमरनाथ** का दूरदर्शन को साक्षात्कार।

'यूथ फ़ॉर परिवर्तन' एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी युवा संगठन है, जिसमें छात्र और कामकाजी पेशेवर शामिल हैं। हमारे संगठन का आदर्श 'स्टॉप कम्प्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग' है। 2014 में, जब बेंगलुरु शहर 'भारत का कचरा शहर' के रूप में सुर्खियों में था, 'यूथ फ़ॉर परिवर्तन' का जन्म उस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हुआ। जिन जगहों में ज्यादा कचरा होने की सम्भावना होती है, उन क्षेत्रों की पहचान करके, उनकी सफाई, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण शुरू करके हमने सार्वजनिक स्थानों को बदलना शुरू किया।

मैं एक वकील हूँ और हमारी टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और विविध पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र हैं। मैं इस अवसर पर हमारी टीम के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समाज के लिए अपना समय निवेश करके जबरदस्त योगदान दे रहे हैं।

हमारा मानना है कि कुछ समय देश और समाज के लिए खर्च करना चाहिए और इसी तरह हमने अपना काम किया है। पिछले आठ वर्षों में अब तक हमने शहर भर में 390 से अधिक स्पॉट फिक्स किए हैं। 'यूथ फ़ॉर परिवर्तन' में हम न केवल स्थानों को बदलने में, बल्कि मानसिकता बदलने में भी विश्वास करते हैं। जब लोग सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सरकार की सम्पत्ति है और इसलिए इसे साफ करना उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम इस मानसिकता को और लोग सार्वजनिक स्थानों को कैसे देखते हैं, इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

हमने कई चुनौतियों का सामना किया है और सबसे चुनौतीपूर्ण स्पॉट वे हैं, जो सफाई के बाद फिर से गंदे हो जाते हैं। जब हम किसी स्थान की सफाई करते हैं तो हम उस स्थान के रखरखाव पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं और यदि हम देखते हैं कि यह फिर से गंदा हो रहा है, तो हम फिर से



सफाई करते हैं और कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि हमने पहली बार दीवार को पेंट किया था, तो अगली बार प्लांटर्स, बेंच आदि स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हम स्थानीय निवासियों और संघों में भी स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए उनको अपने प्रयासों में शामिल करते हैं जो एक तरह से जगह के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने से पहले हमें लोगों से सहायता लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभियान के शुरू होने के बाद एक बड़ा बदलाव आया। स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे काम को मान्यता दी और हमने लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव देखा। अब लोग अपने आस-पास की जगहों की स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश करके अधिक ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। निवासी और संघ सहायक समान स्तर

के उत्साह के साथ स्वच्छता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान अक्टूबर, 2014 में शुरू किया गया था और हमने जून, 2014 में यह पहल शुरू की थी। हमारे आस-पास कई लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हमें 'स्ट्रीट स्वीपर' कहते थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद एक क्रांति शुरू हुई। अब वे सभी लोग हमारी सराहना कर रहे हैं। 'मन की बात' में प्रधानमंत्री द्वारा हमारे संगठन के इस उल्लेख ने हमें नैतिक बढ़ावा दिया है और हमें अपने प्रयासों को जारी रखने और इसे बड़ा बनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री का खुद हमारे काम को पहचानना बहुत बड़ी बात है और इसने हमारे लिए जादू की तरह काम किया है।"

'यूथ फ़ॉर परिवर्तन' के बारे में अधिक जानने के लिए QR कोड स्कैन करें।



# YOUTH FOR PARIVARTHAN®



# लोकल के लिए वोकल

## आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत

“पिछले वर्षों के दौरान, देश का एक नया संकल्प हमारे त्योहारों से जुड़ा है, यह है 'वोकल फ़ॉर लोकल' का संकल्प। अब हम अपने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और व्यापारियों को त्योहारों की खुशी में शामिल करते हैं। यह अभियान इसलिए भी खास है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं।”

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  
(‘मन की बात’ के सम्बोधन में)

“प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ पहल एक महान मंच है, विशेष रूप से छोटे उद्यमियों और व्यवसायों के लिए हमारे उत्पादों को बेचने और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उन्हें बढ़ावा देने के लिए। यह वास्तव में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अग्रणी पहल है।”

-सनी सिंघल  
हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

‘हर भारतीय को वोकल फ़ॉर लोकल होना चाहिए’, यह प्रधानमंत्री का पथप्रदर्शक मंत्र था, जो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता माँगों को पूरा करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान उभरा। प्रधानमंत्री ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाज़ारों और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के संकल्प के रूप में ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ अभियान शुरू किया था। अंततः यह संकल्प हमारे त्योहारों के साथ जुड़ने लगा। जनता से स्थानीय रूप से खरीदारी करने और सभी के बीच त्योहारों की खुशी फैलाने के आग्रह वाले इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों और व्यापारियों के घरों को रोशन करना था। प्रधानमंत्री ने इसका समर्थन करते हुए और ‘आत्मनिर्भरता’ की भावना को मज़बूत करते हुए, भारतीयों को स्थानीय सामान खरीदने और न केवल इनके प्रति ‘मुखर’ होने, बल्कि ‘विश्व स्तर पर’ इन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया है।

हालिया ‘मन की बात’ सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ को सफल बनाने में जनभागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की, “आपको खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प

उत्पाद और अन्य स्थानीय सामान खरीदना चाहिए।”

‘वोकल फ़ॉर लोकल’ बनने के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लोगों ने इस अभियान को बहुत प्रोत्साहन और समर्थन दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान खादी और हथकरघा उत्पादों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है।

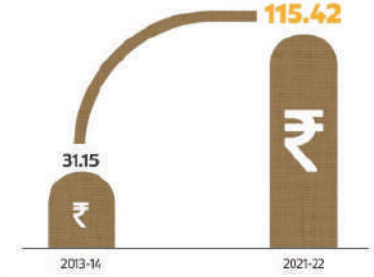
इसी तरह से इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ को अपनाने के लिए देशवासियों को प्रधानमंत्री का आह्वान, उत्सवों में इसे शामिल करने के दिलचस्प तरीकों को सामने लाता है।

एक सुझाव यह है कि त्योहारों के दौरान अपने परिवार और दोस्तों को उपहार के रूप में खूबसूरती से तैयार किए गए स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद दें। ये न केवल आपके प्रियजनों के घरों को रोशन करेंगे, बल्कि कई परिवारों में खुशियाँ लाएँगे। इन उत्पादों की बिक्री उनकी आजीविका का ज़रिया बनेगी।

## खादी की लोकप्रियता नए रिकॉर्ड बनाता

प्रमुख एफएमसीजी को पछाड़कर खादी 1 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली अकेली कंपनी बनी

केवीआईसी वार्षिक टर्नओवर  
(हज़ारों करोड़ रुपये में है क्यूं)



त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को जिम्मेदारी से शामिल करने का एक और तरीका है त्योहारों के दौरान पैकिंग और पैकेजिंग के लिए जूट, कपास और केले के फाइबर बैग का उपयोग करना और हानिकारक प्लास्टिक पॉलीथिन बैग को अलविदा कहना। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वच्छता का ध्यान रखेगा, बल्कि गैर-प्लास्टिक, पारम्परिक बैग के उत्पादन में भी वृद्धि करेगा।



“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद, जो स्थानीय लोगों को न केवल अपने उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बेचने और बढ़ावा देने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें विश्व-स्तर पर निर्यात कर रहा है।”

**-श्री कृष्ण पाल गुर्जर**  
बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री

खादी, सबसे लोकप्रिय भारतीय उत्पादों में से एक है, जिसकी माँग पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है और दुनिया भर में इसकी गूँज है। प्रवासी भारतीय और दुनिया भर के लोग खादी उत्पाद खरीद रहे हैं, उपहार में दे रहे हैं और साथ ही उनका प्रचार भी कर रहे हैं। खादी आज एक बड़ा ब्रांड बन गया है। विभिन्न भारतीय डिज़ाइनरों ने भी हीरो फैब्रिक के रूप में खादी के डिज़ाइनर उत्पाद प्रस्तुत किए हैं। यह समय इन स्थानीय

हीरो उत्पादों के लिए वोकल होकर इन्हें नए क्षितिज तक ले जाने का है।

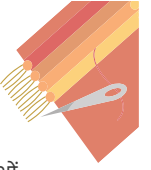
जैसाकि प्रधानमंत्री ने इस सीज़न में स्थानीय खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद कर सभी रिकॉर्ड तोड़ने का आह्वान किया है, तो यह समय ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ के उनके दृष्टिकोण का विस्तार कर ‘लोकल फ़ॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के एक नए युग की शुरुआत करने का भी है।

### प्रधानमंत्री का आह्वान

2 अक्टूबर को बापू की जयंती के अवसर पर हमें इस अभियान को और तेज़ करने का संकल्प लेना है। खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प...इन सभी उत्पादों के साथ आपको स्थानीय सामान जरूर खरीदना चाहिए। आखिर पर्व का असली आनंद तभी है, जब सभी इसका हिस्सा बनें।



## भारत के हैंडलूम



### ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ अभियान को मज़बूत करते

हैंडलूम बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और सबसे जीवंत पहलुओं में से एक है। **भारत दुनिया में हैंडलूम उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है**, जिसका निर्यात 2018-19 में ₹380.4 करोड़ था।

भारत के कुछ बेहतरीन हैंडलूम की एक झलक:

### पैठणी महाराष्ट्र

मराठी साड़ियों की रानी, पैठणी को अपना नाम औरंगाबाद के एक शहर पैठण से मिला। यह मराठा साम्राज्य की शाही महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला परिधान था।



### बांधनी गुजरात

गुजरात का गौरव, बांधनी साड़ियों को हाथ से रंगा जाता है और इसमें कई घंटों का श्रम लगता है। इसे 4,000 से अधिक हाथ से बुनी हुई गाँठों और एक रंगीन मिश्रण से बनाया जाता है।

### कुनबी गोवा

कुनबी गोवा के लोगों की पारंपरिक हाथ से बुनी हुई साड़ी है जिसका आधार चमकदार लाल होता है, जिसे चेक पैटर्न से बेहतर बनाया जाता है।



### मूंगा सिल्क असम

मूंगा सिल्क असम में बनाया और पहना जाने वाला एक मनमोहक वस्त्र है। साड़ी बनाने में 10 या उससे अधिक दिन लगते हैं।

### कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश

कुल्लू शॉल शानदार कपड़े से बने होते हैं, जिसके चारों ओर सुरुचिपूर्ण ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं और इसे पुरुष और महिलाएँ दोनों पहन सकते हैं।



### मैसूर सिल्क कर्नाटक

मैसूर सिल्क बेहद नरम है और इसे जरी और शुद्ध रेशम से बनाया जाता है।

### कलमकारी आंध्र प्रदेश

विभिन्न डिज़ाइनों, रूपांकनों और कहानियों को हाथ से छापकर तैयार की गई इन साड़ियों को कपड़ा उद्योग में अधिक सम्मानित माना जाता है।



### चंदेरी मध्य प्रदेश

चंदेरी एक हल्की और शानदार साड़ी है जिसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से अपना नाम मिला है। साड़ी को एक साथ सुनहरी जरी और रेशम से बुना जाता है।

## वोकल फ़ॉर लोकल के साथ आत्मनिर्भर भारत के एक नए युग की शुरुआत

प्रधानमंत्री की 'वोकल फ़ॉर लोकल' पहल भारत में कई स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों के सपनों को पूरा कर रही है। लोकल के लिए वोकल होने का उनका आह्वान देश के हर क्षेत्र, हर ज़िले और हर राज्य में गूँज रहा है, प्रत्येक अभियान में नवाचार का अपना तत्व जोड़ रहा है।

हुनर हाट जैसी प्रतिष्ठित पहल पुरस्कृत प्लेटफ़ॉर्मों में बदल रही है, जहाँ पारम्परिक कला और शिल्प को वह पहचान मिल रही है, जिसके वे हकदार हैं। देश भर में आयोजित हुनर हाट, स्थानीय कारीगरों को उनके कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने, उनकी आय बढ़ाने और रोज़गार के अवसर उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करने में हुनर हाट को भारत की वास्तविक क्षमता और विरासत को सामने लाने के लिए एक सफल पहल माना जाता है।

हैंडलूम से लेकर हस्तशिल्प तक



और घर के बने व्यंजनों से लेकर जैविक खादी उत्पादों तक हुनर हाट के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया जा रहा है और यह बड़े पैमाने पर पूरे भारत के लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहा है।

विकास को गति देते हुए 'वोकल फ़ॉर लोकल' पहल कई लोगों के जीवन को बदल रही है। जो महिलाएँ काम के रास्ते तलाश रही थीं, अब यह उन्हें और उनके परिवारों को रोज़गार के माध्यम से सशक्त बना रही है।

ऐसे ही कुछ लोगों से दूरदर्शन ने बातचीत की।

'नई दिशा' स्वयं सहायता समूह की गीता ने साझा किया कि, "10-12 महिलाओं के 10 समूहों के साथ हमें अपने घर का बना उत्पाद बेचने, सफल बिक्री करने और पीएम के 'वोकल फ़ॉर लोकल' के माध्यम से कई अन्य महिलाओं के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए एक मंच मिला है। इस पहल ने महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया है।"

यह भारत के बेरोज़गार युवाओं को अपने व्यवसाय को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव मंच बनाकर उद्यम करने में सक्षम बना रहा है। स्थानीय निवासी विवेक, फरीदाबाद में ज़िला परिषद द्वारा आयोजित 'वोकल फ़ॉर लोकल' प्रदर्शनी में भाग लेते हुए साझा करते हैं कि, "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत 'वोकल फ़ॉर लोकल' को बढ़ावा देने के लिए हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और घर का बना सामान, जैसे अचार और पापड़ को बेचने और बढ़ावा देने आए हैं। हम सरस मेले और पीएम मोदी के 'हुनर हाट' में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पीएम द्वारा 'वोकल फ़ॉर लोकल इनिशिएटिव' एक अभिनव योजना है। हम 2016 से इससे जुड़े हुए हैं और आज आय का प्रवाह स्थिर है और हम विभिन्न महिलाओं के लिए रोज़गार पैदा करने में सक्षम हैं, जिनके पास पहले कई अवसर नहीं थे और जो पहले कार्यरत नहीं थीं।"

खादी, एक महत्त्वपूर्ण स्वदेशी ब्रांड को भी 'वोकल फ़ॉर लोकल' अभियान के माध्यम से व्यापक रूप से लोकप्रिय और प्रचारित किया जाता है। खादी ग्राम उद्योग के सनी सिंघल, जो स्किनकेयर से लेकर हेयरकेयर तक हस्तनिर्मित,



जैविक खादी उत्पाद बेचते हैं, साझा करते हैं, "यह योजना छोटे उद्यमियों और व्यवसायों का उत्थान कर रही है। फंडिंग की तलाश करने वाले लोग, जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, विशेष रूप से युवा, जो व्यवसाय में उद्यम करना चाहते हैं, उनके लिए यह सरकार द्वारा दिया गया एक गेम-चेंजिंग प्लेटफ़ॉर्म है और जनता के बीच एक बड़ी सफलता साबित हुई है।"

भारत पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर माँगों को पूरा किया जा रहा है। स्वदेशी उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था को रफ़्तार मिल रही है और भारत में आत्मनिर्भरता का नया सवेरा देखने को मिल रहा है। हालाँकि राष्ट्र का संकल्प है कि न केवल इन हस्तनिर्मित, स्वदेशी उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर भी ले जाना चाहिए। जब भी हम भविष्य में 'वोकल फ़ॉर लोकल' की बात करें, तो उसका अर्थ भारत में बने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से होना चाहिए, जो भारत और दुनिया के लिए हो। आगे बढ़ने का यही हमारा एकमात्र संकल्प और न्यू इंडिया के लिए हमारा विज़न होना चाहिए।

## देश और फ़ैशन के लिए खादी



रितु बेरी

फ़ैशन डिजाइनर

आज सम्पूर्ण राष्ट्र जहाँ पूरे ज़ोर-शोर के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में आज़ादी को परिभाषित करने वाले हरेक विचार पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। आज़ादी को प्रतिबिम्बित करने वाला सबसे बड़ा विचार, जिसने दशकों तक देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखा, खादी है। जब महात्मा गाँधी ने चरखे का इस्तेमाल शुरू किया था, उनका एकमात्र उद्देश्य, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान खादी को प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय तक ले जाना और उनमें राष्ट्रवाद की धारा प्रबल करना था। आज खादी को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक और राष्ट्र का गौरव माना जाता है।

खादी केवल वस्त्र नहीं, विचार है; एक दर्शन है; एक दृष्टिकोण है। विभिन्न तरह के आकार-प्रकार और रंगों में निर्मित खादी सुंदर हस्तनिर्मित

वस्त्र होता है। खादी का आधुनिक स्वरूप सचमुच विलासिता का पर्याय है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ, खादी स्वच्छ और संधारणीय वस्त्र है, जो लम्बा चलता है और उसके साथ काम करना सरल है।

मैंने दीवाली, अन्य त्योहारों और शादी-ब्याहों के लिए खादी के विविध प्रारूप तैयार किए। पहले-पहल इसे राजनीतिज्ञों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही माना जाता था। आज जब मेरे ब्रांड कलेक्शन में खादी के लाल, मरून या फिरोज़ा रंग नज़र आते हैं तो लोग सोचकर हैरान रहते हैं कि क्या यह सचमुच खादी है। एक और रोचक तथ्य यह कि ये कपड़े डिजाइनर कीमतों पर बिकते हैं। मेरा लक्ष्य देश में खादी को विशिष्ट, समृद्ध और ख़ास पहचान देने से जुड़ा है और इसके साथ ही विश्व को यह बताना कि यह हमारा राष्ट्रीय परिधान है और हमें इस समृद्ध धरोहर पर गर्व है।

चूँकि महात्मा गाँधी का इसमें अटूट विश्वास था, चूँकि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी इसे पहनते थे, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज का युवा भारत की आत्मस्वरूप खादी को विशेष बनाने वाले प्रयास को समझे। खादी सामाजिक समानता का भी आदर्श

उदाहरण है; राजनेताओं से विद्यार्थियों तक, पत्रकारों से गृहिणियों तक इसे पहनते हैं। यह ऐसा ब्रांड बन चुका है, जो प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मैंने 'विचार वस्त्र' नामक एक ऐसा कुर्ता तैयार किया, जिसे महिलाएँ और पुरुष; दोनों पहन सकते हैं।

गत कई वर्षों से खादी और ग्राम उद्योग कमीशन (केवीआईसी) की सलाहकार के तौर पर मैंने खादी से जुड़े कई मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने के प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री के 'वोकल फ़ॉर लोकल' नज़रिए के अनुसार, खादी ग्राम उद्योग के बुनकरों द्वारा कड़ी मेहनत से बनाए गए कपड़े को भारतीय जनमानस तक ले जाने का मैंने निरंतर प्रयास किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खादी ब्रांड हर घर में प्रचलित है। समूचे राष्ट्र ने एक साथ खादी पर बात करनी शुरू कर दी है। उन्होंने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रत्येक व्यक्ति को खादी के महत्त्व के बारे में बताया है और आज फ़ैशन जगत में खादी को आगे ले जाने वाले पहले व्यक्तियों में शामिल रहने पर मैं 'फ़ैशन के लिए खादी, राष्ट्र के लिए खादी और परिवर्तन के लिए खादी' के प्रधानमंत्री के मंत्र से बेहद प्रेरित हूँ।

साथ ही आगामी कल के चलन स्थापित करने वाले युवा द्वारा खादी पहनना अब अभियान सरीखा बन गया है। छोटे क्षेत्रों और राज्यों में रहने वाले लोग

भी इस अभियान में शामिल हुए और इसे सही मायने में 'जनआंदोलन' का रूप दिया है।

देश भर के डिजाइनरों के सामने खादी को वैश्विक स्तर पर ले जाने की चुनौती सामने आई है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। केवीआईसी में हमने देश के शीर्षस्थ डिजाइनरों के सामने खादी को उनकी विशेषज्ञता अनुसार इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव रखा। वैश्विक मंचों पर विभिन्न डिजाइनरों ने खादी को प्रस्तुत किया है। 1960 के दशक में मोहनजीत ने पेरिस में खादी की पहचान कराई थी। इसी तरह ऑट कोटूर में वैशाली एस ने भारत की बुनाई को प्रदर्शित किया। यह तथ्य पहचान कराता है कि भारतीय डिजाइनर, भारत की बुनाई और खादी की वैश्विक स्तर पर पहुँच बना रहे हैं और इस तरह साझा प्रयासों से हम 'लोकल फ़ॉर ग्लोबल' को चरितार्थ कर सकते हैं।

मैं सभी भारतीयों से अपील करती हूँ कि उनके पास खादी का एक परिधान अवश्य हो, जिसे वे किसी महत्त्वपूर्ण अवसर पर पहनें, ताकि लोग खादी की सुंदरता को पहचानें और इसकी समृद्ध धरोहर से अवगत हों, साथ ही नए कल के रचनाकार के तौर पर युवाओं को खादी का अनुभव और उसे सहयोग ज़रूर करना चाहिए। इस दीवाली भारत के स्थानीय बुनकरों के घरों में उजाला करने और भारत भर में हर्षोल्लास की लहर फैलाने के लिए हमें इस उत्सव में खादी को ज़रूर शामिल करना चाहिए।



## सेवा परमो धर्मः

जन भागीदारी से बदल रहा देश का भविष्य

“दूसरों का हित करने के समान, दूसरों की सेवा करने, उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। लोग आगे आकर किसी-ना-किसी टीबी के पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं। दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरण जानने को मिला है, जहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गाँवों को गोद लिया है। परोपकार की यह भावना गाँवों में रहने वालों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आई है।”

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  
(‘मन की बात’ के सम्बोधन में)

“कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोगों की सक्रिय भागीदारी और एकजुटता के बिना सफल नहीं हो सकता है। 2025 का लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, इसलिए टीबी की समाप्ति के लिए हर क्षेत्र के लोगों को साथ आकर इसे जन-आंदोलन बनाना होगा।”

—डॉ. विनोद पॉल  
सदस्य, नीति आयोग

“परहित सरिस धरम नहीं भाई।” अर्थात् दूसरों की भलाई के समान अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। कवि तुलसीदास कृत *श्रीरामचरित मानस* की इस पंक्ति का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने हालिया ‘मन की बात’ सम्बोधन में किया। वे समाज सेवा और परोपकार की भावना के महत्त्व और उदाहरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे।

भारतीय संस्कृति में सदैव समाज सेवा को सर्वोपरि माना गया है, चाहे वह वेद व्यास का ‘परोपकारः पुण्याय’ हो, हमारे ऋषि-मुनियों की ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः’ की कामना, या मैथिलीशरण गुप्त का ‘वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे’ का लेखन – सभी ने परहित, यानी कि दूसरों के हित को ही धर्म माना।

प्रधानमंत्री प्रायः स्वयं को देश का ‘प्रधान सेवक’ कहते हैं। आज उनके मार्गदर्शन से सरकार द्वारा कई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनकी बुनियाद जन भागीदारी है। स्वच्छ भारत अभियान, मिशन अमृत सरोवर, वोकल फ़ॉर लोकल - इन सभी पहलों की नींव है जन भागीदारी और स्वयं से ऊपर उठकर अपने समुदाय, अपने समाज के लिए सेवा भाव। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में लोग एक-दूसरे की मदद करने सामने आए।

‘सबका प्रयास’ के मूल मंत्र से प्रेरित एक उदाहरण टीबी-मुक्त भारत अभियान की ‘नि-क्षय मित्र’ पहल प्रारम्भ होने पर देखने को मिल रहा है जिसके अंतर्गत कई लोगों ने टीबी रोगियों को ‘गोद’ लेने का बीड़ा उठाया है। नि-क्षय मित्र कोई भी व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट, निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है और टीबी से जूझ रहे मरीजों को सरकार द्वारा की जा रही मदद के अलावा पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता दे सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नि-क्षय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ टीबी मरीज स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं और नि-क्षय मित्र इस पोर्टल से जुड़कर टीबी रोगियों को एक सामान्य जीवन व्यतीत करने में सहायता कर सकते हैं।

लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते यह हम सब का दायित्व है कि हम अपने समुदाय और अपने समाज को रहने के

लिए एक उपयुक्त स्थान बनाएँ और ऐसा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और स्वेच्छा से उसकी उन्नति के लिए कार्यरत रहे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परहित से ही किसी भी समाज की नींव पड़ती है।

परंतु सामाजिक उत्तरदायित्व का सार किताबों में या किसी के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता। इसे सीखने और आत्मसात करने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है और भारत जैसे युवा देश में यह जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। किशोरावस्था से ही समाज सेवा की भावना को जगाने हेतु भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) चलाती है। ‘नॉट मी बट यू’ के अपने आदर्श के साथ, एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा प्रदान करने का अनुभव कराना है।

आज के युवा इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भली-भाँति समझ

# मैं नहीं हम



रहे हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने 50 गाँवों को गोद लिया है। ग्रामवासियों को विभिन्न बीमारियों से बचने के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ बीमारी के समय में मदद करने और सरकारी योजनाओं के बारे में गाँवों के लोगों को अवगत कराने का कार्य ये छात्र कर रहे हैं।

'Self4Society' के आधार पर 2018 में 'मैं नहीं हम' पोर्टल को लॉन्च किया गया, जो एक मंच बना उन आईटी पेशेवरों और संगठनों के लिए जो सामाजिक मुद्दों और समाज की सेवा में कार्यरत हैं। यह पोर्टल आज समाज के कमजोर वर्गों की सेवा में, खासकर प्रौद्योगिकी के फ़ायदों के ज़रिए, सहयोग को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, "अनेक अवसरों पर जब 'सरकार' कुछ नहीं कर पाती है, तो उसे 'संस्कार' कर दिखाते हैं।" सरकार नागरिकों के हित के लिए अनेक योजनाएँ लेकर आ सकती है, लेकिन किसी भी पहल को सफलता उसमें शामिल लोगों की भागादारी से ही मिलती

“हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में हमारे इस विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम का उल्लेख किया।”

**-रूपाली बरिया**

छात्रा, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, सिलवासा

है। राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सरकार के प्रयासों के साथ-साथ हर नागरिक की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्तर पर साथी देशवासियों के कल्याण के लिए अपना योगदान दे।

अपने 'मन की बात' सम्बोधनों में अनेक बार प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपना समूचा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आंध्रप्रदेश के मक़पुरम के राम भूपाल रेड्डी हों, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई करीब 100 बच्चियों की शिक्षा के लिए दान कर दी, या आगरा, उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह, जिन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि अपने गाँव तक मीठा पानी पहुँचाने के लिए



सौंप दी; रुद्रप्रयाग के मनोज बैजवाल, जो पिछले 25 वर्षों से पवित्र स्थलों को प्लास्टिक-मुक्त करने में भी जुटे हुए हैं, या देवर गाँव की चम्पादेवी, जिन्होंने सैकड़ों पेड़ लगाकर एक हरा-भरा वन तैयार कर दिया है, हमारे देश में ऐसे अनगिनत लोग हैं, जिन्होंने स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा के मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाया हुआ है।

जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छाशक्ति हो, तो बड़े-से-बड़े लक्ष्य को पाना संभव हो जाता है। समाज-सेवा का कार्य सबके लिए एक गर्व का विषय होना चाहिए और इस भावना को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने पद्म पुरस्कारों को 'पीपुल्स पद्म' का रूप दिया है, जिससे



उन लोगों का सम्मान हुआ, जिनके अथक प्रयासों से उनके समुदायों में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।

अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गम्भीरता हो, तो एक व्यक्ति भी पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। आज जब भारत एक ग्लोबल सुपरपावर बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो ज़रूरी है कि हर नागरिक सशक्त बने, समाज को सशक्त करे और परिणामस्वरूप देश को सशक्त करे और यह तब होगा, जब हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का अनुसरण करेंगे और एक परिवार की तरह एक-दूसरे के लिए खड़े होंगे। 'अमृत काल' में प्रवेश करते हुए यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए।



## टीबी-मुक्त भारत अभियान : जन-जन का कर्तव्य

प्रधानमंत्री ने हालिया 'मन की बात' सम्बोधन में टीबी-मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल 'नि-क्षय मित्र' का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का आधार जनभागीदारी और कर्तव्य भावना है। 2025 तक भारत के टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई लोग स्वेच्छा से इस पहल का हिस्सा बन रहे हैं और टीबी मरीजों को गोद ले रहे हैं।

ऐसी ही एक शख्स हैं **प्रियंका प्रियदर्शिनी**। "मैंने कोविड लॉकडाउन के दौरान 'मन की बात' कार्यक्रम को फॉलो करना शुरू किया। 25 सितम्बर के अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्रीजी ने देशवासियों से भारत को टीबी-मुक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की, तो मैंने भी सोचा कि इसमें बढ़-चढ़ के अपना योगदान दूँ। 8 अक्टूबर को मैंने विजयनगर टीबी यूनिट सेंटर, ग़ाज़ियाबाद से पाँच मरीजों को पोषण-सम्बन्धी सहायता प्रदान करने हेतु गोद लिया। मैंने संकल्प लिया है कि मरीजों के ट्रीटमेंट के दौरान मैं उनकी पूरी सहायता करूँगी।"

रोटरी क्लब, इंदिरापुरम के **डॉ. दीपक भार्गव** कहते हैं, "टीबी के मरीज को अगर

उचित पोषण, दवाइयाँ और देखभाल मिले, तो वह एक स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। हमने 1,000 लोगों का टारगेट रखा है और इनमें बच्चे और बड़े दोनों हैं। ऐसे मरीज भी हैं, जो मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट टीबी से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री का 2025 तक भारत को टीबी-मुक्त बनाने का लक्ष्य हमने भी अपना लिया है।"

गुजरात के बारडोली में स्थित दीवालीबेन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, **नलिन जोशी** बताते हैं, "हम सरकार के साथ मिलकर टीबी मरीजों की मदद करने का काम कर रहे हैं। हमें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने सम्पर्क किया और कहा कि हम सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को और बढ़ावा दें। उन्होंने हमसे प्रोटीन-बेस्ड इम्युनिटी बूस्टर प्रोवाइड करने के लिए कहा ताकि मरीजों की रिकवरी जल्दी हो सके। हम अब सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक साल तक टीबी के 100 मरीजों को ये बूस्टर निःशुल्क नियमित रूप से मिलें। हम आशा करते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री के टीबी-मुक्त भारत अभियान से हम जुड़े हैं, वैसे ही और गैर सरकारी संगठन भी आगे आएँ और सहयोग दें।"



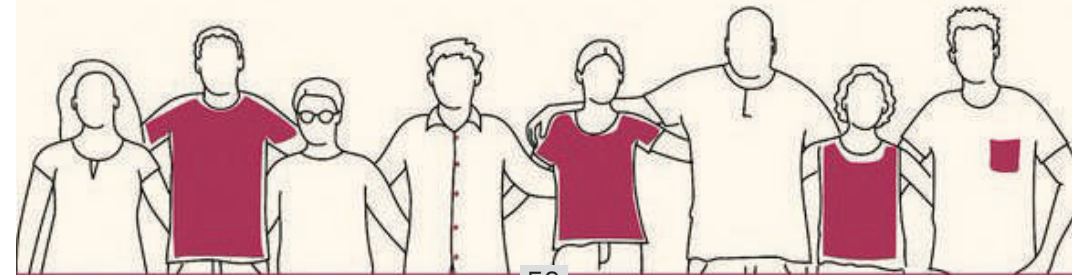
**विराट कोहली**

क्रिकेटर

टीबी-मुक्त भारत अभियान में जनभागीदारी के महत्त्व पर क्रिकेटर **विराट कोहली** के विचार।

"नमस्ते मित्रो! मैं विराट कोहली। अपने हालिया 'मन की बात' सम्बोधन में प्रधानमंत्रीजी ने समाज की सेवा के महत्त्व के बारे में बात की। मेरा मानना है कि समाज सेवा की भावना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब टीबी-मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में, लोग आगे आ रहे हैं, टीबी रोगियों को अडॉप्ट कर रहे हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। इलाज योग्य होने के बावजूद टीबी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमणात्मक मृत्यु का कारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने

वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसलिए सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे टीबी-मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता दें। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन पहल है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम सभी को हमेशा समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। मैं आप सभी से टीबी-मुक्त अभियान में शामिल होने और दुनिया को जनभागीदारी की शक्ति दिखाने की अपील करता हूँ।"



# टीबी उन्मूलन के लिए जन-आंदोलन



**डॉ. विनोद पॉल**  
सदस्य, नीति आयोग

2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति के निर्धारित वर्ष 2030 की समय सीमा से पाँच साल पहले ही वर्ष 2025 तक देश से टीबी समाप्त किए जाने का आह्वान किया था। इसके बाद ही टीबी-मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए रोगी-केंद्रित, व्यापक और उत्तरदायी राष्ट्रीय रणनीतिक योजना शुरू की गई। टीबी का पता लगाने, इसकी रोकथाम करने, टीबी मरीजों के उपचार और उनकी बाद की देखभाल जैसे अनेक परिवर्तन करके इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया गया।

देखा गया कि बड़ी संख्या में रोगी निजी क्षेत्र में उपचार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन टीबी प्रणालियों से पूरी तरह न जुड़े होने के कारण उनकी कारगर देखभाल में बाधा आ रही है। इससे निपटने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसे पेशेवर संगठनों के साथ मिलकर, देश

भर में टीबी के अधिक रोगियों वाले 350 से अधिक जिलों में प्रभावी प्रणालियाँ शुरू की गईं ताकि देखभाल के स्रोत की परवाह किए बिना सभी रोगियों को मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित हो सके। कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करके इस पहल से निजी क्षेत्र में टीबी मामलों की सूचनाएँ मिलने में तेज़ी से सुधार हुआ (2014 में लगभग 1 लाख मामले और 2019 में 6.6 लाख)।

इसके अलावा, निदान सम्बन्धी क्षमता के उन्नयन और विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। आज 3,700 से अधिक उन्नत मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब हैं। देश के हर ज़िले में देश में ही विकसित किए गए ऐसे उपकरण हैं, जिनसे नैदानिक सेवाएँ लोगों को उनके आस-पास ही उपलब्ध करवाई गई हैं।

सरकार ने बैडाक्वीलीन और डेलामानिड जैसे नए, सुरक्षित और उपचार की छोटी अवधि वाली औषधियाँ उपलब्ध करवाने में भी तेज़ी दिखाई, जिससे दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के उपचार के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत टीबी रोगी को उपलब्ध सहायता का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता को भी समझा गया और उपचाराधीन सभी रोगियों को प्रत्यक्ष नक़द लाभ के माध्यम से पोषणपूर्ति के लिए नि-क्षय पोषण योजना शुरू की गई।

भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिन्होंने प्रत्येक टीबी रोगी की देखभाल सम्बन्धी पूरे काम पर डिजिटल रूप से नज़र रखने तथा ज़मीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सूचना भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक

प्रणाली तैनात की है। आईटी प्लेटफॉर्म, नि-क्षय लाइव राष्ट्रीय डाटा भण्डार के रूप में कार्य करता है, जिसकी मदद से कार्यक्रम से जुड़ी टीम उन्नत विश्लेषण कर पाती है और टीबी महामारी विज्ञान, उपचार कवरेज और कार्यक्रम के कामकाज को समझने के लिए एक विशाल संसाधन भी मिलता है। कार्यक्रम के कुछ तत्वों को मज़बूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वाले समाधान भी तलाशे जा रहे हैं, जैसे एक्स-रे स्क्रीनिंग, नैदानिक परीक्षणों की स्वतः रीडिंग, हॉटस्पॉट मैपिंग आदि। इन नए विकल्पों से सटीक उपचार कर पाने की अत्यधिक सम्भावना है।

कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोगों की सक्रिय भागीदारी और एकजुटता के बिना सफल नहीं हो सकता है। 2025 का लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, इसलिए टीबी की समाप्ति के लिए हर क्षेत्र के लोगों को साथ आ कर इसे जन-आंदोलन बनाना होगा। इसके लिए समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों, विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, बड़े व्यवसायी एवं उद्योगपतियों, जानी-मानी हस्तियों, मीडियाकरमियों और सामुदायिक नेताओं पर टीबी उन्मूलन को अपना समर्थन देने की विशेष जिम्मेदारी है।

पिछले महीने भारत के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान', टीबी रोगियों की देखभाल में समाज की सदभावना का लाभ उठाने की एक अनूठी पहल है। इस आंदोलन का उद्देश्य समुदायों को टीबी उन्मूलन मिशन के लिए एकजुट करना है। 'पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान' का उद्देश्य व्यक्तियों से लेकर संगठनों तक के लोगों को उपचाराधीन टीबी रोगियों से जोड़ना है। इन रोगियों की मदद के इच्छुक लोग स्वयं चुन सकते हैं कि वे रोगी को किस तरह यानी अतिरिक्त पोषण देने में,

अतिरिक्त निदान और जाँच करवाने अथवा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के रूप में मदद करना चाहेंगे।

एक महीने से भी कम समय में इस पहल को जिस तरह की अद्भुत प्रतिक्रिया मिली, वह दिल को छू लेने वाली है। इस अभियान के तहत 10 लाख टीबी रोगियों के एक समूह ने सहायता लेने को सहमति व्यक्त की। जवाब में 28,000 से अधिक नि-क्षय मित्र (दाता) सामने आए, जो 9.8 लाख (97 प्रतिशत) से अधिक टीबी रोगियों को मदद देंगे। यह भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने और सबसे ज़रूरतमंदों की देखभाल के लिए हमारे उदार समाज की प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण है।

यह पहल हमारे अन्य प्रयासों के साथ-साथ चलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अगर हमारी जानकारी में कोई टीबी से पीड़ित है तो उन्हें उचित उपचार लेने में मदद करें। लम्बे समय तक खाँसी रहना या टीबी के अन्य लक्षण होने पर शुरुआती इलाज़ लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इस के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होगी। ऐसे लोगों का एक्स-रे और अन्य परीक्षण करवाने और उपचार शुरू करवाने में मदद देने आगे आएँ। मीडिया इस बीमारी से जुड़ा कलंक दूर करने में और भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमें विशेष रूप से अपनी जनजातीय आबादी तक पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके सुदूर इलाके और परिवार की निर्धनता विशेष चुनौतियाँ पेश करते हैं। आदिवासी कल्याण विभागों और ग्रैर-सरकारी संगठनों को इस मिशन के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है।

हम टीबी समाप्त करने के लक्ष्य के करीब हैं। प्रभावी कार्यक्रम और मज़बूत जन-आंदोलन के बल पर हम इसे आसानी से हासिल कर सकेंगे।

# भारत में टीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है सामुदायिक उत्तरदायित्व



**पूनम खेत्रपाल**

क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण-पूर्व एशिया, WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की आठ प्रमुख प्राथमिकताओं, सतत विकास लक्ष्यों और टीबी के वैश्विक अंत की रणनीति के अनुरूप, 2030 तक टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण हैं।

टीबी के इलाज के लिए 1944 से ही एक प्रभावी एंटीबायोटिक उपलब्ध है। हालाँकि टीबी के खिलाफ लड़ाई ने परम्परागत रूप से एक जैव चिकित्सा दृष्टिकोण का पालन किया है, जो गरीबी और कुपोषण जैसे प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों से अलग है।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी पर स्वास्थ्य व्यय के तौर पर मोटी रकम खर्च

की जाती है। इस क्षेत्र में टीबी-प्रभावित अनुमानित 30-80 प्रतिशत परिवार मुफ्त टीबी निदान और उपचार सेवाओं को प्राप्त करने के बावजूद बड़ी राशि व्यय करते हैं।

कोविड-19 महामारी ने टीबी के सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों को गहन बना दिया है, इस क्षेत्र के लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है और कुपोषण को बढ़ा दिया है। एक अनुमान के अनुसार 2019 में इस क्षेत्र में टीबी के लगभग एक मिलियन नए मामले सामने आए हैं।

आज और आने वाले महीनों तथा वर्षों में इन निर्धारकों का पता लगाना और टीबी-प्रभावित समुदायों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है और इस दिशा में भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है।

अक्टूबर 2021 में क्षेत्र के देशों—भारत, इंडोनेशिया और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए कार्रवाई को नवीनीकृत करने, 2018 के दिल्ली End TB शिखर सम्मेलन की प्रतिबद्धता और क्षेत्र की कार्रवाई पर विचार किया गया।

सदस्य देशों ने 2030 तक टीबी को समाप्त करने की दिशा में एक नई क्षेत्रीय कार्यनीतिक योजना का भी समर्थन किया, जिसमें इस समुदाय के नेतृत्व वाली निगरानी, टीबी गर्वनेस में भागीदारी एवं सहभागिता कानून और नीति में सुधार के साथ-साथ नकद अंतरण और पोषण सम्बन्धी सहायता सहित सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल हैं।



2020 में प्रधानमंत्री के टीबी को समाप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई को 'जन आंदोलन' में बदल दिया है। 2018 में शुरू की गई नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। 2021 में रोगी सहायता गतिविधियों के लिए वित्तीय परिव्यय 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था।

साथ ही 'प्रधानमंत्री टीबी-मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत सितम्बर 2022 में शुरू किया गया 'Adopt a TB Patient' (एक टीबी रोगी को अपनाएँ) अभियान, सभी टीबी रोगियों को अतिरिक्त पोषण सहायता और मुफ्त निदान उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। दवाएँ पहले से प्रदान की जा रही हैं। इससे,

अधिक-से-अधिक रोगियों को उपचार पूरा करने, इस कलंक से छुटकारा पाने और टीबी-प्रभावित परिवारों के भारी खर्च कम करने में मदद मिलेगी।

जी-20 के अगले अध्यक्ष के रूप में भारत के पास 2030 तक टीबी को समाप्त करने की लड़ाई में अपने वैश्विक नेतृत्व को बढ़ाने और 2023 में इस बारे में संयुक्त राष्ट्र की उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान अपनी कई उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर है।

मैं भारत की सफलता की कामना करती हूँ और सभी भारतीयों को टीबी-मुक्त भारत, टीबी-मुक्त दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र और टीबी-मुक्त दुनिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरंतर सहयोग का आश्वासन देती हूँ।

## मेडिकल के छात्रों का अनोखा प्रयास 'विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम'

केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव प्रशासन ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया है, 'विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम', जिसके अंतर्गत नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, सिलवासा के एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने 50 गाँवों को गोद लिया है। प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-सम्बन्धी एवं अन्य सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एमबीबीएस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया है।

हमारी दूरदर्शन टीम ने इस पहल से जुड़े लोगों से बात की।



जीनु रावतिया

नमो मेडिकल कॉलेज की छात्रा **राखी दूबे** कहती हैं, "हर शनिवार, 10 छात्रों के गुट में हम अपने मेंटर अध्यापकों के साथ, बिंद्राबीन गाँव में आते हैं। गाँव में हम हर उम्र के लोगों की जाँच करते हैं। छोटे बच्चों में अनीमिया, कुपोषण हो या जिन माँओं को एंटे नेटल व पोस्ट नेटल केयर की ज़रूरत हो, हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं। बड़े-बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, और टीबी की भी जाँच करते हैं, साथ ही स्वास्थ्य-सम्बन्धी जो भी योजनाएँ हैं, उनकी जानकारी भी हम गाँव वालों को देते हैं, जिससे उन्हें काफी फ़ायदा हुआ है। गीले और सूखे कचरे को कैसे अलग-अलग रखना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, हम इसके बारे में भी गाँव वालों को बताते हैं।" राखी ने बताया कि उनके प्रयासों के कारण ग्रामवासियों ने एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया है, जिसका प्रभाव गाँव वालों में दिखता है।

विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम के दौरान एमबीबीएस की छात्रा **रूपाली बरिया** का अनुभव भी अनोखा रहा है। "वैसे तो एमबीबीएस के पाँच वर्षों के बाद इंटरनशिप के दौरान गाँवों में जाकर सीखने को मिलता है। अभी मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम के कारण अलग-अलग गाँवों में जाकर जो लोगों के जीवन के बारे में पता चला, वह बहुत ही अच्छी बात है। हमने ही सिर्फ़ गाँव वालों को नहीं सिखाया, बल्कि उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे कम से कम संसाधनों के साथ वे रहते हैं। जो शायद इंटरनशिप में जाकर सीखने



को मिलता, वह सब हमें सीखने का मौका मिला है। हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में हमारे इस विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम का उल्लेख किया।"

केंद्रशासित प्रदेश के विकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक **डॉ. वी.के. दास** ने बताया, "हमने कॉलेज के 500 बच्चों को 50 गाँवों में 10-10 के बैचेज में बाँटा। इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई और हर शनिवार उन्हें अपने अलॉटिड गाँवों में जाकर पूरा काम करना है, जैसे बेसिक सर्वे का काम, लोगों को बीमारियों और स्वास्थ्य-सम्बन्धी और अन्य कई सरकारी योजनाओं (जैसे PM-AWAS, किसान क्रेडिट कार्ड) के बारे में जागरूक करना आदि।"

"हमने यह निर्णय लिया है कि जिस छात्र को जो गाँव अलॉट होगा, वह पाँच वर्षों तक उसी गाँव की ज़िम्मेदारी लेगा। इससे यह होगा कि छात्र का उस गाँव से लगाव

तो होगा ही, साथ ही गाँव वाले भी उस छात्र को अच्छे से पहचानने लगेंगे, जिससे इंटरैक्शन आसान होगा। गाँवों के बच्चे, जो इन छात्रों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वे प्रोत्साहित हो रहे हैं कि वे भी आगे चल के ऐसा काम कर सकते हैं।" डॉ. दास ने कहा।

अपना अनुभव साझा करते हुए, नमो मेडिकल कॉलेज के छात्र **गर्वी चौधरी** ने कहा, "शहरी लोगों के विपरीत, ग्रामीण अक्सर स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने से हिचकिचाते हैं। इसलिए प्रशासन ने तय किया कि यदि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा सकते, तो उन्हें मेडिकल छात्रों के ज़रिए स्वास्थ्य सुविधाएँ अवश्य ही मिलनी चाहिए।"

इन छात्रों का कार्य देख कर बिंद्राबीन गाँव की एक आदिवासी महिला **जीनु रावतिया** ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कार्य से अवगत कराया, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में भी किया। ग्राम निवासी **सूरज** ने बताया, "जीनु बेन ने मुझसे कहा कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हमारे गाँव बिंद्राबीन में आने से उन्हें जो लाभ मिला है और स्वास्थ्य में बेहतरि हुई है, उसके बारे में वे प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखना चाहती हैं। छात्रों के प्रयासों से जीनु बेन के स्वास्थ्य में बेहतरि हुई है और उन्होंने सोचा कि क्यों इस अच्छी पहल के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पहुँचाया जाए। पत्र उन तक पहुँचा और उन्होंने इसका ज़िक्र अपने 'मन की बात' सम्बोधन में किया और हमारे गाँव का भी नाम लिया, उसके लिए हम उनका और एडमिनिस्ट्रेटर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।"

'विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम' के बारे में अधिक जानने के लिए QR कोड स्कैन करें।



## शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में कम होता विभेद



प्रफुल पटेल

प्रशासक, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल में बेहद छोटे हैं और यहाँ से एमबीबीएस के सेंट्रल पूल में केवल एक सीट आरक्षित हुई थी। इसलिए केंद्रशासित प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र को 177 छात्रों की क्षमता वाले एक मेडिकल कॉलेज का उपहार दिया था। उनकी दूरदर्शिता के लिए केंद्रशासित प्रदेश सदा प्रधानमंत्री का ऋणी रहेगा।

गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके समग्र विकास के प्रधानमंत्री के लक्ष्य से प्रेरित होकर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में स्थापित नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एमबीबीएस के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम'

की विशेष पहल को शामिल किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जहाँ वे गोद लिए गए स्थानीय परिवारों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। इस सर्वांगीण कार्यक्रम की शुरुआत गाँववासियों और मेडिकल स्टूडेंट्स, दोनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है। कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य गाँव वालों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना और उनके बीच केंद्र एवं केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनस्वास्थ्य एवं समाज कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। बेहतर जीवनशैली के लिए छात्र गाँव वालों को इन योजनाओं के अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करते हैं। परिवारों के साथ छात्रों के परस्पर आदान-प्रदान से उनके सम्प्रेषण और सामाजिक व्यवहार की योग्यता में भी वृद्धि होती है। कार्यक्रम के चलते अंततः शहरी व ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में विभेद कम होगा, वहीं मेडिकल छात्रों को अपने गाँवों में निरंतर काम करते देख गाँव के बच्चे भी उच्चशिक्षा की ओर उन्मुख होंगे, जिससे गाँवों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

'विश्व स्वास्थ्य दिवस' के अवसर पर 7 अप्रैल, 2022 को दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में 'विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम' का उद्घाटन करना मेरा सौभाग्य था, जिस दौरान 506 मेडिकल छात्रों ने पचास गाँवों को गोद लिया था। इसके अंतर्गत, सप्ताह में एक बार एक शिक्षक और एक शिक्षकेत्तर अध्यापक के साथ दस छात्रों का दल गोद लिए गाँवों में जाते हैं। इस दौरान

छात्र पीआरआई सदस्यों से बात करते हैं और वहाँ बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों आदि जैसे कमज़ोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिवारिक सर्वेक्षण करते हैं, साथ ही, वे पोषण से जुड़ी आदतों, बच्चों के बीच टीकाकरण के महत्त्व, बच्चों में कुपोषण दूर करने, गर्भवती महिलाओं की जन्मपूर्व देखभाल, पर्यावरण स्वच्छता, नशा छुड़ाने, परिवारों में एनीमिया, संक्रमण और गैर-संक्रमण वाले रोगों की जाँच और ज़रूरत पड़ने पर रोगियों को निकटवर्ती स्वास्थ्य सेवा केंद्र भेजते हैं।

छात्रों द्वारा आरम्भिक जाँच में गाँवों में मोतियाबिंद के कई मामले मिले, जिन्हें निकट के स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जरी के लिए भेजा गया। उन्हें वरिष्ठ लोगों में हाइपरटेंशन और मधुमेह के लक्षण भी मिले, जिन्हें खुद अपने रोगों का अंदाज़ा नहीं था और उनके उपचार की भी शुरुआत हुई।

छात्रों ने पाया कि आँगनवाड़ी में भर्ती बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य जाँच और देखभाल की आवश्यकता थी, इसलिए, स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा 303 आँगनवाड़ियों में और डीएनएच में 17,356 बच्चों की जाँच हुई। कम और अधिक कुपोषण के शिकार बच्चों का उपचार शुरू हुआ या इलाज के लिए भेजा गया। इसी तरह कम उम्र से ही स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्वास्थ्य जाँच की विस्तृत योजना को प्रोत्साहन दिया गया।

परिवारों और सरकारी तंत्र के बीच सेतु बनकर उन्होंने परिवारों को विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण योजनाओं की

सुविधाएँ प्राप्त करने में मदद की। इसके चलते प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री नि-क्षय योजना जैसी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूकता और समझदारी में वृद्धि हुई। केंद्रशासित प्रदेश की डिकरी विकास योजना, परिपक्व माता नियोजित बाल योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, साँझ हेल्थ कार्ड और अटल पेंशन योजना जैसी पहलों को भी प्रश्रय दिया गया।

एमबीबीएस के समूचे कोर्स के दौरान छात्रों को नियमित अंतराल पर गोद लिए परिवारों के पास जाना होता है, जिससे इन परिवारों के साथ लम्बा और भरोसेमंद सम्बन्ध बनता है, जिसके आधार पर समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलती है।

मुझे हाल में बिंद्राबीन गाँव की एक जनजातीय महिला श्रीमती जीनु रावतिया का बेहद संवेदशील पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने छात्रों द्वारा किए जा रहे असाधारण कार्यों की तारीफ की। पत्र में उन्होंने छात्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों और उसका उनके परिवार एवं गाँव पर पड़े असर पर विस्तार से लिखा। उन्होंने इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री की गहरी दूरदृष्टि का परिणाम बताया और योजना को सफलतापूर्वक अमल में लाने के लिए केंद्रशासित प्रशासन का धन्यवाद दिया था।



# मिरेकल मिलेट्स

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत-प्रायोजित प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों के समर्थन मिलने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' सम्बोधन में श्रोताओं से मिलेट्स की अपनी रेसिपीज़ साझा करने को कहा। उन्होंने यह भी सुझाया कि इस तरह के सभी व्यंजनों को एक ई-बुक में संकलित कर MyGov प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जा सकता है।



आइए कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में जानते हैं जिन्हें मिलेट्स का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है।

## सांवा और मखाने की खीर

सामग्री

- सांवा: 50 ग्राम
- मखाना: 50 ग्राम
- दूध: 100 मिलीग्राम
- घी: 1 बड़ा चम्मच
- चीनी: 150 ग्राम
- इलायची पाउडर: एक चुटकी
- जायफल पाउडर: एक चुटकी
- बादाम के टुकड़े: 2 बड़े चम्मच
- पिस्ते के टुकड़े : 2 बड़े चम्मच
- काजू : 2 बड़े चम्मच
- केसर: एक चुटकी

## प्रक्रिया

- सांवा को ठंडे पानी में धोकर 5 मिनट के लिए भिगो दें, और धोकर पानी निकाल दें।
- एक भारी तले के पैन में घी गरम करें और मखानों को हल्का क्रिस्पी होने तक भुनें।
- मखानों को पैन से निकाल दें और उसी पैन में दूध डालें।
- दूध में उबाल आने दें और भीगे हुए सांवा को डालकर पकने दें (लगातार चलाते रहें)।
- भुने हुए मखाने को मिक्सी में दरदरा पीस लें और दूध में उबाले हुए सांवा में मिला दें।
- अब चीनी डालें और खीर को और 5 मिनट तक पकाते रहें।
- केसर, काजू, इलायची और जायफल पाउडर डालें।
- एक-दो मिनट के बाद आँच बंद कर दें।
- खीर को सर्विंग बाउल में डालें और बादाम और पिस्ते के स्लाइस से सजाएँ।

## कुटकी की खिचड़ी

सामग्री

- कुटकी: 500 ग्राम
- हरा चना: 200 ग्राम
- प्याज़: 25 ग्राम
- हरी मिर्च: आवश्यकता अनुसार
- तेल/घी: 50 ग्राम
- सब्ज़ियाँ (बींस, फूलगोभी, आलू, गाजर, आदि): 400 ग्राम
- टमाटर: 100 ग्राम
- करी पत्ता: थोड़ा सा
- धनिया पत्ती: 50 ग्राम
- सरसों के बीज: 5 ग्राम
- ज़ीरा: 5 ग्राम
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: 5 ग्राम
- नमक: स्वादानुसार



कुटकी की खिचड़ी



सांवा और मखाने की खीर

## प्रक्रिया

- हरे चने को धोकर एक कटोरे में 30 मिनट के लिए भिगो दें।
- कुटकी को धोकर एक कटोरे में निकाल लें।
- प्याज़, हरी मिर्च और सब्ज़ियाँ काट लें।
- एक मध्यम आकार का पैन लें और उसमें तेल/घी गरम करें।
- राई, ज़ीरा, करी पत्ता, कटे हुए प्याज़, हरी मिर्च डालें और धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट तक भुनें।
- अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर धीमी आँच पर 2 मिनट तक भुनें।

- सभी सब्ज़ियाँ, हल्दी पाउडर, टमाटर डालें और धीमी आँच पर 5-10 मिनट के लिए भुनें।
- हरा चना, पानी डालें और मध्यम आँच पर पानी में उबाल आने तक गर्म करें।
- जब पानी में उबाल आने लगे तो पैन में थोड़ी सी कुटकी डालें। स्वादानुसार नमक डालें।
- पैन को ढक कर 20-25 मिनट तक पकाएँ।
- बीच-बीच में चलाते रहें और देख लें कि कुटकी पक गया है या नहीं।
- पक जाने के बाद आँच बंद कर दें। कटी हुई धनिया पत्ती से सजाकर परोसें।



## विकास खन्ना

प्रोफेशनल शेफ़

मिलेडस के महत्त्व और पारम्परिक व्यंजनों के बारे में शेफ़ विकास खन्ना के विचार।

“यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के कारण वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेडस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह अद्भुत है! मिलेड एक ऐसा अनाज है, जो न केवल हमारे ग्रह के लिए, बल्कि हमारे शरीर और हमारे दिमाग के लिए भी सूपर सस्टेनेबल है।

‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने घरेलू

और पेशेवर रसोइयों से मिलेडस का उपयोग कर अपने पेशेवर और आधुनिक व्यंजनों के साथ-साथ पारम्परिक व्यंजनों को साझा करने का आग्रह किया है और मैं भी लोगों से अपने व्यंजनों को साझा करने का आग्रह करता हूँ, ताकि व्यंजनों के इस ब्रेनपूल को एक ई-बुक में संकलित किया जा सके, जिसे हम दुनिया के साथ साझा कर सकें।”

मिलेडस के बारे में लोगों की राय जानने के लिए QR कोड को स्कैन करें।



# मिलेडस बन रहे हैं आम लोगों की पसंद

दूरदर्शन से बातचीत में लोगों ने मिलेडस के फ़ायदों के बारे में चर्चा की।  
आइए जानते हैं, क्या कहना है उनका

“घरेलू स्तर पर बहुत तरह के उत्पाद हैं, जो मिलेडस द्वारा बनाए जाते हैं। बाजरे की ढूँढी या लड्डू, जिन्हें देशी घी और तीसी मिला कर बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आजकल आप अगर फ़ाइट स्टार होटल्स में जाएँ तो वहाँ तमाम तरह की कुकीज़ मिलेडस से बनती हैं, जो कि स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होती हैं। बाजरे या दूसरे मिलेडस से बनी खिचड़ी भी पसंद की जाती है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें करीब 59 देशों ने भाग लिया था। वहाँ हर दिन मिलेडस द्वारा बनाए गए व्यंजन उन्हें परोसे गए और उनके पोषक तत्वों के बारे में भी जानकारी दी गई।”

– डॉ. ए.के. सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

“मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मिलेडस को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों से आग्रह किया है कि वे इन फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। मिलेडस हमारे देश की धरोहर हैं और बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं। इनसे कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरे जैसे प्रोफेशनल शेफ़्स जब इन डिशेज़ को एक अच्छा रूप देंगे, एक अच्छा सलाद बनाएँगे, अच्छी मिठाइयों का रूप देंगे, और मॉडर्न प्रेज़ेंटेशंस करेंगे, तो बहुत सारे लोग मिलेडस को अपनाएँगे और खाएँगे। अब तो संयुक्त राष्ट्र ने भी 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेडस वर्ष घोषित किया है, तो आओ जुड़ें और मिलेडस को और आगे बढ़ाएँ।”

– डॉ. परविंदर सिंह बाली, कॉरपोरेट शेफ (एल एंड डी), ओबेरॉय होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के परिणामस्वरूप अगला वर्ष मिलेडस के प्रोत्साहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी और सार्थक पहल है। मिलेडस हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इन अनाजों के सेवन को प्रोत्साहित करेंगे तो इनकी खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान और भी बढ़ेगा। अगर हम मिलेडस की स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाएँगे तो इससे विश्व में इनकी माँग भी बढ़ेगी और भारत में उत्पादित मिलेडस का बड़े स्तर पर निर्यात भी किया जा सकेगा।”

– डॉ. अजय जोशी, निवासी, बीकानेर



# मन की बात

प्रतिक्रियाएँ













PM Modi Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने बताई योग की महत्वता, मन की बात में सुनाई अन्वी की प्रेरणादायक कहानी

## हि हिन्दुस्तान

'सिर्फ 2 शब्द कहूंगा और 4 गुना बढ़ जाएगा जोश', आखिर PM मोदी ने 'मन की बात' में ऐसा क्या कहा?

## जनसत्ता

Mann ki Baat: चीतों को किस नाम से बुलाया जाए- पीएम मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव

## नईदुनिया

Mann Ki Baat Highlights: चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब होगा भगत सिंह एयरपोर्ट, मन की बात में पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बातें

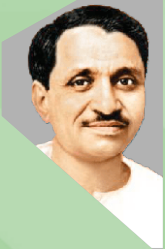




स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागम  
Clean Coast, Safe Sea



NATIONAL TUBERCULOSIS ELIMINATION PROGRAMME  
एन.टी.बी.निवृत्ति  
एन.टी.बी.निवृत्ति



ॐ



सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार